RNI No. DELMUL/2012/47011

14 जुलाई, 2026 मंगलवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 103

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

रमीज ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे से पहले कप्तान बदलने पर उठाये सवाल 07

संक्षिप्त वार्ता

सभा में नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक आई उनका गला भर आया

वेब वार्ता, दतिया। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव में टिकट न मिलने का गम सह नहीं पा रहे हैं यह आज भी देखने को मिला जब दतिया में बीजेपी की सभा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक गईं। उनका गला भर आया, आवाज भर्रा उठी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा- कांग्रेस कहती है कि भाजपा में फूट है। देख लीजिए, हम सब यहां साथ खड़े हैं। मैं इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताने दतिया के एक-एक घर के सामने शीश नवाऊंगा।

नरोत्तम ने कहा- कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह यानी राजा साहब एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली हैं। वो बहुत मीठी होती है, लेकिन असर कुछ नहीं होता। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- नरोत्तम, हम छोटे भाई आशुतोष तिवारी को आपके सुपुर्द कर रहे हैं। आज पूरे उत्साह के साथ बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब ढाई बजे नामांकन भरा। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित दूसरे पार्टी नेता उनके साथ रहे।

एम्स की रिसर्च स्त्री रोग जांच में बीमारी ही नहीं,महिलाओं का डर भी समझेंगे डॉक्टर

वेब वार्ता, भोपाल। स्त्री रोग की जांच के दौरान महिलाओं की झिझक, डर और अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पाने की समस्या भी अब बेहतर इलाज की राह तय कर सकती है। एम्स भोपाल की रिसर्च ने महिला मरीजों के अनुभव, आशंकाओं और अपेक्षाओं को जांच का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत बताई है। रिसर्च का फोकस इस बात पर है कि केवल बीमारी की पहचान ही नहीं, बल्कि जांच के दौरान महिला की गरिमा, सहमति और उससे प्रभावी संवाद भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी है।

एम्स भोपाल के नर्सिंग कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉ. नसीमा शफकत ने मध्य भारत की महिलाओं के स्त्री रोग परीक्षण से जुड़े अनुभव और आशंकाओं पर अध्ययन किया है। इसमें यह समझने की कोशिश की गई कि जांच को लेकर महिलाओं के मन में क्या चिंताएं रहती हैं और वे डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों से किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। रिसर्च ने प्रभावी संवाद और सूचित सहमति की जरूरत को प्रमुखता से रेखांकित किया है।

राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र

उप्र सरकार, ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, वेब वार्ता। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को अब तक की जांच की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में एसआईटी के बारे में भी उल्लेख करने को कहा गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी की स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने को टालने का अनुरोध किया, जिसे पीठ ने अस्वीकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं में से एक के अधिवक्ता ने न्यायालय से सीसीटीवी फुटेज और अन्य अभिलेख सुरक्षित रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी की रिपोर्ट की प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन पीठ ने फिलहाल इससे इनकार करते हुए कहा कि जांच जारी है और इस पर बाद में विचार किया जाएगा। एक याचिका नरेन्द्र कुमार गोस्वामी ने स्वयं दायर की है, जिसमें सीबीआई जांच के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने की मांग की गयी है।

दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है। इसमें भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को श्रद्धालुओं एवं दानदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि आरोप अंतत: सही साबित हों या नहीं, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्टों से राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करने वाले और दान देने वाले लोगों में व्यापक चिंता पैदा हुई है। तीसरी जनहित याचिका राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की है। इसमें उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के अलावा ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेनदेन का फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की गयी है।

नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से होना चाहिए: उच्चतम न्यायालय

27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला रद्द, सभी प्रकरण नए सिरे से सुनवाई के लिए विदेशी न्यायाधिकरण को लौटाए

उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता और विदेशी होने के निर्धारण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय केवल निष्पक्ष, वैधानिक और उचित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने असम से जुड़े 27 मामलों में दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उन आदेशों को निरस्त कर दिया, जिनमें विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने के निर्णय को बरकरार रखा गया था। शीर्ष न्यायालय ने सभी मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नागरिकता अथवा विदेशी होने का निर्धारण अत्यंत संवेदनशील विषय है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का वास्तविक और प्रभावी अवसर मिलना चाहिए। केवल औपचारिक प्रक्रिया अपनाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी तो न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक है। केवल तकनीकी आधार पर नागरिकता से जुड़े अधिकारों का निर्धारण न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार का यह वैध और आवश्यक दायित्व है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं, वे गलत दावों या न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब का लाभ उठाकर नागरिकता प्राप्त न कर सकें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संबंधी मामलों में कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि विदेशी न्यायाधिकरण ने संबंधित 27 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया था। इसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि संबंधित व्यक्ति नोटिस मिलने के बावजूद न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने लगभग 23 वर्ष बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारतीय नागरिकता सिद्ध करने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर ही होता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को नागरिकता संबंधी विवादों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में विदेशी न्यायाधिकरणों और प्रशासनिक एजेंसियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा तथा नागरिकता से जुड़े मामलों में निष्पक्ष सुनवाई, प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा।

बॉक्स : फैसले की प्रमुख बातें

- नागरिकता पर सर्वोच्च अदालत की अहम टिप्पणी
- नागरिकता का निर्धारण केवल निष्पक्ष, वैधानिक और उचित प्रक्रिया से ही किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का वास्तविक और प्रभावी अवसर देना अनिवार्य।
- केवल तकनीकी आधार पर किसी को विदेशी घोषित करना न्यायसंगत नहीं।
- उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक।
- सरकार का दायित्व है कि अपात्र व्यक्ति गलत दावों के आधार पर नागरिकता प्राप्त न कर सकें।
- कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी।

सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सत्र के सुचारु संचालन और विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले विधायी एजेंडे की रूपरेखा साझा कर सकती है। वहीं विपक्ष अपने प्रमुख राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों को बैठक में उठाने की तैयारी कर रहा है।

पब में लगी आग: जान बचाने टॉयलेट में छिपे वहीं पिघल गए, 27 की मौत

हादसे में 63 झुलसे, 22 की हालत गंभीर

वेब वार्ता, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में रविवार देर रात भीषण आग लगने से कम से कम 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 63 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 22 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बैंकॉक के चाटुचाक डिस्ट्रिक्ट में स्थित रॉन्ग बीयर ना लाट प्राओ बार में रात करीब 11 बजकर 57 मिनट पर हुआ। हादसे के बाद तुरंत हरकत में आए दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पब के मुख्य दरवाजे से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं और लोग जान बचाने के लिए अफरा-तफरी में भागते नजर आ रहे हैं, जबकि आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा था। घटनास्थल पर पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस संगीतकार से बात की थी जो आग लगने के समय परफॉर्म कर रहा था। संगीतकार ने बताया कि आग आउट स्विच के पास लगी थी और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से हुए, धमाके होने लगे और सभी लोग धुएं और लपटों से दूर भाग रहे थे। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि कई लोग इसलिए भी नहीं बच पाए, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पाए। इसकी वजह थी कि वे बिल्डिंग के पीछे चले गए थे और धुएं और लपटों से बचने के लिए टॉयलेट में छिपने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं हमें सबसे ज्यादा शव मिले हैं। यह मंजर बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था, जहां लोग मौत से बचने के लिए आखिरी कोशिश में थे।

शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स रखे

आग पर काबू पाए जाने के बाद, बार के बाहर बड़ी संख्या में शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स रखे थे, जो त्रासदी की भयावहता को बयां कर रहे थे। वहीं, अंदर का पूरा फर्नीचर, दीवारें और सीलिंग जलकर काले हो गए थे और टूटकर गिर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब भी बड़ी संख्या में लोग गायब हैं, जिनकी तलाश जारी है।

दतिया उपचुनाव
कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दाखिल किया नामांकन

दतिया, (वेब वार्ता)

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया है।

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह सबसे पहले पीतांबरा पीठ पहुंचे और मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक फूल सिंह बरैया, जिला अध्यक्ष अशोक दांगी सहित वरिष्ठ कांग्रेसजनों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया।

नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारी फाइट भाजपा से है। आजाद समाज पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, उनको कोई वोट नहीं देगा। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि हम कांग्रेस को जिताएंगे।

बसपा नहीं लड़ रही दतिया उपचुनाव, सपा कांग्रेस के साथ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दतिया उपचुनाव से दूरी बनाते हुए मध्य प्रदेश इकाई को साल 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के एमपी प्रभारी राजाराम, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल के साथ मिलकर कैडर मैनेजमेंट को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इस अंचल में समाजवादी पार्टी 'इंडिया गठबंधन' के धर्म का पालन कर रही है। पार्टी इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह का खुला समर्थन करेगी।

नागपुर में संपन्न हुई ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक

वेब वार्ता, नागपुर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक का सफल समापन व्यापक मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। चार दिनों तक चली इस बैठक को सदस्य देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में पारित घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे में चक्रीयता (सकुर्लैरिटी), सतत विमानन ईंधन (एसएएफ), परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण, शहरी गतिशीलता केंद्रों के विकास, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला सहयोग तथा ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क को मजबूत करने जैसे प्रमुख विषयों पर साझा दृष्टिकोण

और सहयोग का खाका प्रस्तुत किया गया है।

बैठक में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान सदस्य देशों ने आपसी सम्मान, समानता और आम सहमति की भावना के साथ विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी देशों ने परिवहन क्षेत्र में टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक व्यवस्था विकसित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक के सफल आयोजन और सकारात्मक परिणामों के लिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी देशों की रचनात्मक भागीदारी और सहयोग के कारण साझा घोषणापत्र पर सर्वसम्मति बन सकी, जो भविष्य में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेगा।

भारत ने बैठक के दौरान यह भी दोहराया कि वह ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता को इन पहलों और कार्यक्रमों का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा, ताकि अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। चार दिवसीय कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, परिवहन मंत्रियों का सम्मेलन, विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें तथा तकनीकी विचार-विमर्श आयोजित किए गए। इसके साथ ही ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

देश में मानसून ने भरी हुंकार: बिहार-बंगाल में रेड अलर्ट

वेब वार्ता, नई दिल्ली। देशभर में मानसून अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर से होते हुए हिसार, मेरठ, शाहजानकारी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और दक्षिण असम तक फैली हुई है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ और बिहार-बांग्लादेश के ऊपर बना साइक्लोनिक सकुर्लेशन (चक्रवाती परिसंचरण) मानसून को अतिरिक्त ताकत दे रहे हैं। यही वजह है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए भारी बारिश वाले साबित हो सकते हैं।

इंडोनेशिया से आया ऑर्डर: टाटा-महिंद्रा बनाएंगे मिसाइलें

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन को नई गति देने के लिए एक अहम नीतिगत फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक अस्त्र मार्क-2 एयर-टू-एयर मिसाइल के उत्पादन में पहली बार निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया जाएगा, जिसमें टाटा समूह, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज और आईकॉम जैसी कंपनियां भाग ले सकेंगी। यह कदम भारत को रक्षा उत्पादन और हथियार निर्यात के क्षेत्र में नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

सरकार इस परियोजना में वही मॉडल अपना रही है, जिसे पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एएमसीए परियोजना में अपनाया गया है। इस मॉडल के तहत मिसाइल का डिजाइन और तकनीक सरकारी एजेंसियों के पास रहेगी, जबकि बड़े पैमाने पर निर्माण का जिम्मा निजी कंपनियां संभालेंगी। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, सेना की जरूरतें समय पर पूरी होंगी और निर्यात ऑर्डर भी तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। वर्तमान में अस्त्र मिसाइल का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) करती है, लेकिन सशस्त्र बलों की बढ़ती मांग और विदेशों से संभावित ऑर्डर को देखते हुए अकेले बीडीएल के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। निजी कंपनियों के जुड़ने से नई उत्पादन इकाइयों का विकास होगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनेगी और मिसाइलों की डिलीवरी में तेजी आएगी।

...बढ़ती मांग भी एक महत्वपूर्ण कारण है

सरकार के इस फैसले के पीछे विदेशी बाजारों से बढ़ती मांग भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों में रुचि दिखाई है। लगभग 180 से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क-2 एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को आंखों से दिखाई देने की सीमा से पहले ही निशाना बनाने में सक्षम है। इसे भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क-1ए, मिग-29, सुखोई-30 एमकेआई और नौसेना के राफेल मरीन लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अस्त्र मार्क-2 को चीन की लंबी दूरी की पीएल-15ई एयर-टू-एयर मिसाइल का प्रभावी जवाब माना जा रहा है। इसकी उन्नत सीकर तकनीक और लंबी मारक क्षमता भारतीय वायुसेना को सामरिक बढ़त प्रदान करेगी। सरकार की योजना केवल अस्त्र मार्क-2 तक सीमित नहीं है।

ईरान-अमेरिका तनाव : 150 डॉलर तक जाएगा कच्चा तेल

वेब वार्ता, नई दिल्ली। आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिले तब हैरान मत होना। ईरान और अमेरिका के बीच गहराता तनाव कच्चे तेल की कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जा रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मौजूदा हालात नहीं सुधारने पर 110 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की गई है। सोमवार को वैश्विक तेल कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज हुई। इस उछाल ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 13 जुलाई को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.34 डॉलर बढ़कर 79.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 3.07 डॉलर चढ़कर 74.20 डॉलर प्रति बैरल हुआ। पिछले सप्ताह भी दोनों बेंचमार्क में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और यूरोपीय प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स में भी 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

संपादकीय

अब ट्रंप की हत्या का युद्ध

राष्ट्रपति ट्रंप ने 36 घंटे में पांच बार धमकियां दी हैं कि यदि ईरान ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की, तो अमरीका उसे तबाह कर देगा, मिट्टी मलबा कर देगा। इसके लिए उन्होंने अमरीकी सेना को आदेश भी दे दिए हैं। पेंटागन एक लंबे साल तक ईरान पर हमले करने और बमबारी करने की तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि 1000 मिसाइल लॉक और लोडेड कर दी गई हैं। अर्थात उनके निशाने तय कर दिए गए हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की गई, तो ईरान पर मिसाइलों और ताकतवर बमों की बारिश कर दी जाएगी। ईरान को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई है कि उनके पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई और जंग में मारे गए लोगों का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। यह ईरानी अवाम की मांग और भावनाएं भी हैं। मुज्तबा ने ट्रंप और नेतनयाहू को दुश्मन करार दिया है। सुप्रीम लीडर के फरमान से साफ है कि दोनों की हत्या की जाए। सुप्रीम लीडर ने, अंततः, यहां तक कहा, हम रहें या न रहें, लेकिन बदला हर हाल में लिया जाएगा। ट्रंप और मुज्तबा के बयान बेहद भयानक और खौफनाक हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की जाती है अथवा ईरान की साजिश वाली रणनीति कामयाब हो जाती है, तो अमरीका और ईरान ही नहीं, दुनिया के एक बड़े भूभाग में प्रलय मच जाएगी। विश्लेषकों के आकलन हैं कि ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेल चुकी है। ऊर्जा, गैस, खाद्य, मशीनरी, उर्वरक की आपूर्ति बाधित है, तो विश्व में ऐसे संकटों का भी तनाव बना रहेगा। अभी तक देशों ने अपने रिजर्व तेल भंडारों का इस्तेमाल किया है और युद्ध समाप्त होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यदि देशों के तेल भंडार भी खत्म होने लगेंगे, तो कच्चे तेल की कीमतें कौनसे आसमान तक जाएंगी, उनका अनुमान अभी संभव नहीं है।

भारतीय अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि यदि युद्ध 3-4 सप्ताह और खिंच गया, तो कच्चा तेल 120-140 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत को भी आर्थिक-ऊर्जा संबंधी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। अभी तक गोदाम भरे थे, लिहाजा कोई चिंता नहीं थी, लेकिन गोदाम खाली होने के बाद कुल नुकसान 950 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह भारत की कुल जीडीपी से दोगुना से भी अधिक है। दरअसल बुनियादी सवाल यह है कि क्या ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को मारने का रोडमैप तक तैयार कर लिया है अथवा इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की रपट के आधार पर ही हत्या की धमकियां दी जा रही हैं? किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष की जिंदगी पर मौत के भयावह साए मंडराते ही रहते हैं लेकिन ट्रंप पर राष्ट्राध्यक्ष बनने से पहले और बाद में जानलेवा हमले किए गए हैं। यहां तक खबरें हैं कि ईरान ने अमरीका में ही अपने स्लीपर सेल्स सक्रिय कर दिए हैं। मेक्सिको के ड्रग्स तस्करों से भी बातचीत की खबरें सामने आई हैं, क्योंकि वे भी राष्ट्रपति ट्रंप के धुर विरोधी हैं और उनके गिरोह बेहद ताकतवर और हत्यारे माने जाते हैं। बहरहाल हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते। फिर भी सवाल है कि क्या ऐसी साजिशें भी अमरीकी राष्ट्रपति की हत्या कर सकती हैं? अमरीका ने अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गैरीफील्ड, विलियम मैकिनले, जॉन एफ कैनेडी सरीखे चार राष्ट्रपतियों के हत्याकांड देखे और झेले हैं, लिहाजा ट्रंप की सुरक्षा में अतिरिक्त, कड़े, बहु लेयर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया एजेंसियों की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। अमरीका का भी इस युद्ध में 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है। उसके एमक्यू-9 ड्रोन तबाह हुए हैं। उसके लड़ाकू विमान ध्वस्त किए गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि यदि अमरीका को ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने की नौबत देखनी पडी, तो कमोबेश 10 लाख सैनिक चाहिए। और इतने सैनिक अमरीका बलिदान नहीं दे सकता। जमीनी लड़ाई के बिना अमरीका युद्ध नहीं जीत सकता। यदि ट्रंप की हत्या का बयान भी खोखला नारा साबित हुआ और ट्रंप का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो एक मलाल शेष रह जाएगा। ईरान का वजूद फिर भी बरकरार रहेगा।

चुनौतियों के बीच निर्यात बढ़ाता भारत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राओं के दौरान इन तीनों देशों के साथ हुई व्यापारिक वाताओं से निर्यात के नए अध्यायों की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। 6 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रभावी व्यापार वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को इंडोनेशियाई बाजार में विस्तार देने पर बातचीत हुई। भारतीय जेनेरिक दवाओं के इंडोनेशिया में निर्यात को बढ़ाने के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर करने पर समझौता हुआ। भारतीय कृषि उत्पादों और कृषि तकनीक के निर्यात के लिए नए रास्ते खोले गए। आस्ट्रेलिया में 8 से 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी के बीच मुख्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक हितों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को पूरी तरह लागू करने के लिए इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की समयसीमा तय की गई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध आपूर्ति पर समझौता हुआ। परमाणु और हरित ऊर्जा के साथ-साथ भारत के कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात पर सकारात्मक बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा 10 से 11 जुलाई तक हुई। इस दौरान ऐतिहासिक व्यापारिक वार्ता हुई। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, जिसका मुख्य एजेंडा व्यापारिक गतिरोधों को तोड़ना था। दोनों देशों ने आगामी वर्षों के लिए व्यापार का एक स्पष्ट खाका तैयार किया। दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं (टैरिफ और गैर-टैरिफ) को हटाने पर गंभीर चर्चा हुई। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर सहमति बनी ताकि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, दवाओं और प्रसंस्कृत खाद्य (कृषि उत्पादों) का न्यूजीलैंड में निर्यात तुरंत बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि इस समय जब वैश्विक निर्यात की वृद्धि दर में कमी आते हुए दिखाई दे रही है, तब भारत निर्यात बढ़ाने के साथ इस वर्ष निर्यात के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में सभी राज्यों के औद्योगिक संगठनों से कहा कि सरकार के द्वारा निर्यात की राह को आसान बनाया जा रहा है और भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल एक लाख करोड़ डॉलर (एक ट्रिलियन डॉलर) के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात का लक्ष्य लगभग 530 अरब डॉलर (16-17 प्रतिशत वृद्धि)

और सेवा निर्यात का लक्ष्य लगभग 470 अरब डॉलर (11-12 प्रतिशत वृद्धि) अनुमानित है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर था। यह बात महत्वपूर्ण है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में वस्तु निर्यात में 15 प्रतिशत और सेवा निर्यात में 11 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय सरकार के द्वारा जहां निर्यात बढ़ाने की रणनीति के तहत निर्यातकों को विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं, वहीं अब सरकार छोटे उद्योगों के अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन का खर्च ह्यनिर्यात संवर्धन मिशनह्न के तहत उठाएगी।

सरकार के द्वारा सतत टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल और मेडिकल टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों को चिन्हित किया गया है। सरकार के द्वारा एफटीए के इस्तेमाल हेतु फ्रेमवर्क की निर्धारित नई रणनीति के तहत जिन क्षेत्रों में भारत पहले से ही उल्लेखनीय रूप से निर्यात कर रहा है, उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाना, तरजीह शुल्क मिले हुए सेक्टर में निर्यात का विविधीकरण करना, गैर शुल्क बाधाएं कम करना तथा आपूर्ति से जुड़ी कमियों को दूर करना शामिल हैं। पिछले माह भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीइटीए) की समीक्षा के बाद कहा गया है कि यह समझौता 15 जुलाई से कार्यान्वित होगा। इससे भारत और ब्रिटेन दोनों लाभान्वित होंगे। खासतौर से भारत से निर्यात बढ़ेंगे एवं भारतीय पेशेवरों के लिए ब्रिटेन के बाजार में अवसर बढ़ेंगे। विगत 17 जून को फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमरीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द आकार लेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि जी-7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने वार्ता के दौरान कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही कार्यान्वित होगा। नि:संदेह भारत एफटीए की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं और यह जल्द ही पूर्णतया लागू होगा। न्यूजीलैंड के साथ किए गए इस एफटीए का अत्यधिक मजबूत पक्ष भारत से सेवा निर्यात बढ़ाना और भारत से पेशेवरों को न्यूजीलैंड में अच्छे अवसरों के लिए आगे बढ़ाना भी है। यह एफटीए भारत की प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए एक मजबूत बुनियाद प्रदान करता है। साथ ही अब ओमान, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रहे एफटीए के और अधिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि इस समय दुनिया के विकसित और विकासशील देश तेजी से भारत के साथ कारोबार बढ़ाने के मद्देनजर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात के नए बाजार और निर्यात विविधता की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चिन्हित किए गए नए देशों के निर्यात बाजारों में अपनी निर्यात पैठ बनाने के हरसंभव उपाय करने होंगे।

वर्तमान में भारत से कुल निर्यात का अधिकांश भाग अमरीका, यूएई, ब्रिटेन, सऊदी अरब और चीन जैसे कुछ प्रमुख देशों पर निर्भर है। अतएव अब ऐसे देशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसी एक या कुछ देशों में आर्थिक सुस्ती का सीधा असर भारत पर न पड़े। अब पारंपरिक बाजारों के अलावा, उत्तर पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे नए उभरते क्षेत्रों तक निर्यात पहुंच तेजी से बढ़ाना होगी। निर्यात विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। हमें निर्यात बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ कई बातों पर ध्यान देना होगा। अब अल्पकालिक वृद्धि के पीछे भागने के बजाय, भारत को मध्यम अवधि की राजकोषीय और बाह्य स्थिरता को सुरक्षित रखना होगा। लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। एआई जैसे उच्च-स्तरीय क्षेत्रों में निवेश, मजबूत डिजिटल अधोसंरचना और नियामक बाधाओं को बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से आसान बनाना होगा, जो सीमाओं के पार सेवा निर्यात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकें। निर्यातकों की दिक्कतों को कम करना होगा। ये दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं, वरन् निर्यात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क से भी संबंधित हैं। घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और गैर-टैरिफ बाधाएं दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

डा. जयंती लाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

साम्राज्वाद के विरोध में ईरान का प्रतीकः बंद मुट्ठी

ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई की पिछले दिनों 4 से 9 जुलाई के मध्य हुई विश्व की सबसे बड़ी अंत्येष्टि को दुनिया ने देखा। लगभग एक सप्ताह तक चले अंत्येष्टि के इस आयोजन में ईरान व इराक में लगभग दो हजार किलोमीटर की शवयात्रा निकाली गयी, करोड़ों की भीड़ को विभाजित करने के लिये तेहरान साहित कई प्रमुख शहरों में नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई गयी। यह ऐतिहासिक जनसैलाब न केवल अमेरिका इस्राईल के मिसाईल हमले में शहीद अपने रहबर व उनके शहीद परिजनों को रोते बिलखते हुये श्रद्धांजलि दे रहा था बल्कि भारी गुस्से का भी इजहार कर रहा था। लाखों लोग बदले का प्रतीक लाल परचम उठाये हुये थे जबकि सैकड़ों बैनर पोस्टर पर अंग्रेजी में किल ट्रंप लिखकर अमेरिका को ईरानियों का सीधा सन्देश भी दिया गया था। गम और गुस्से के संदेशों से भरे इन्हीं परचमों,पोस्टर्स व बैनर्स के बीच एक विशेष प्रतीक ने भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह था बंद व बुलंद मुट्ठी का प्रतीक। खबर है कि शहादत के वक़्त भी उनकी मुट्ठी बंधी हुई थी।

दरअसल बंद मुट्ठी का अर्थ आम तौर पर प्रतिरोध, एकजुटता, और संघर्ष को जारी रखने का संकेत होता है। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के संदर्भ में इसे उनके समर्थकों व राजनीतिक व धार्मिक पक्षों की तरफ से यह संदेश माना गया कि वे उनकी विरासत, उनके विचार और ईरान की मौजूदा सत्ता-रचना के साथ खड़े हैं। इतिहास गवाह है कि बंद मुट्ठी दुनिया भर में पहले भी कई वैश्विक आंदोलनों में खासकर साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध और दृढ़ता का प्रतीक रही है। इस प्रतीक को केवल शोक का ही नहीं, बल्कि ह्लहम पीछे नहीं हटेंगेह्न हम डटे रहेंगे व हमारा संकल्प दृढ़ है,हम संगठित हैं जैसे राजनीतिक संदेशों के रूप में भी समझा जाता है। इसी तरह खामनेई की शहादत के बाद जो पोस्टर लगाए गए, उनमें बंद मुट्ठी को उनकी सत्ता, विचारधारा और समर्थक नेटवर्क की निरंतरता के प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया। इसका आशय यह भी हो सकता है कि उनके अनुयायी इसे केवल मृत्यु नहीं, बल्कि संघर्ष और प्रतिरोध के नए चरण की शुरूआत मान रहे हैं। वैसे भी दास्तान-ए-करबला से प्रेरणा लेने वाली शिया कौम में राजनीति और प्रतीकों में शोक, प्रतिशोध और न्याय की भाषा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए ऐसी छवियाँ भावनात्मक रूप से यह भी कहती हैं कि समुदाय अपने नेता की ह्लशहादतह्न या मृत्यु को निजी दुख के साथ-साथ सामूहिक संकल्प में बदल रहा है। बंद मुट्ठी का मतलब यह भी है कि हम शोक में तो जरूर हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं और हम विरोध का अपना रास्ता भी जारी रखेंगे। बंद मुट्ठी का प्रतीक यह भी दशार्ता है कि हम कमजोर, बिखरे हुये या नेतृत्व-हीन नहीं हैं बल्कि हमारा संगठन, विचारधारा और सामूहिक अनुशासन अभी भी मजबूत है।

पोस्टर और प्रतीक केवल तर्क से नहीं, भावना से भी काम करते हैं। बंद मुट्ठी, शोक को क्रोध, स्मृति और प्रतिशोध की राजनीति में बदल देती है, जिससे समर्थकों में एक सामूहिक पहचान और ह्लहम बनाम वेह्न की भावना मजबूत होती है। ऐसे पोस्टर आंतरिक सत्ता-संघर्ष में भी काम आते हैं, क्योंकि वे उत्तराधिकार या नेतृत्व-रिक्ति के समय समर्थकों को एक धुरी के चारों ओर इकट्ठा करते हैं। इससे जनता को यह संदेश जाता है कि सत्ता या व्यवस्था अभी भी नियंत्रण में है और बिखराव नहीं हुआ। आम तौर पर ऐसे प्रतीक तीन स्तरों पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं। एक तो सड़क पर समर्थकों का मनोबल बढ़ाने में,दूसरा नेतृत्व की वैधता दिखाने और तीसरे अपने विरोधियों को यह संकेत देने में कि संघर्ष वैचारिक रूप से जारी रहेगा। इसलिए इसे केवल एक चित्र नहीं, बल्कि राजनीतिक संचार की रणनीति समझना चाहिए। साथ ही बाहरी दुनिया के लिए भी यह प्रतीक एक तरह की चेतावनी है कि ईरान-समर्थक धड़ा किसी भी स्वयंभू महाशक्ति के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान में शहीद खामनेई की अंत्येष्टि में करोड़ों शोकाकुल लोगों के बीच इस तरह के संकेत का पोस्टर बैनर्स में नजर आना साथ ही बार बार उपस्थित करोड़ों लोगों द्वारा गुस्से में यही प्रतीक बनाकर और बुलंद कर व अमेरिका, इजराइल के विरुद्ध गगनचुंबी नारे लगाकर प्रतिद्वंद्वियों को सीधा संदेश दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उनके खास सहयोगी देश इस्राईल के साम्राज्वादी इरादों को दुनिया देख ही रही है। गजा,फिलिस्तीन,लेबनॉन,स ीरिया,यमन,ईरान,इराक,वेनेजुएला आदि अनेक देशों को बर्बाद करने में अमेरिका इस्राईल ने कोई कसर बाक ी नहीं राखी। जब चाहे जिस देश को चाहें धमकियाँ देते रहते हैं। यहाँ तक की देश पर कब्जा करने की भी धमकी दे बैठते हैं। यह साम्राज्यवादी देश, दूसरे देशों की धन सम्पदाओं,प्राकृतिक संसाधनों यहाँ तक कि उनपर बलात कब्जा जमाकर उनकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने की सोच रखते हैं। और अपने इन नापाक इरादों को पूरे करने के लिये बांटो और राज करो,पड़ोसी देशों में भय और अविश्वास पैदा करने जैसे घिनौने खेल खेलते हैं और इसी की आड़ में अपने हथियार बेचते हैं। दुनिया के तमाम देश इनकी ताकत की वजह से इनसे सीधे टकराव नहीं चाहते। परन्तु ईरान ने विश्व इतिहास में अब तक के इस मिथक को मिटा दिया है कि इन साम्राज्यवादी देशों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सैन्य ताकत से लेकर राजनैतिक व कूटनीतिक सभी क्षेत्रों में स्वयंभू सर्वशक्तिमान अमेरिका,इस्राईल व इनका साथ देने वाले उसके सभी सहयोगियों को दिखा दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुये बंद मुट्ठी की ताकत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को भी घुटनों पर ला सकती है।और अब दुनिया यह स्वीकार करने लगी है कि विश्व व्यवस्था अब सम्रज्यवादी अमेरिका के इशारों पर नहीं चलने वाली। ऐसे में सवाल यहउठता है कि क्या अब खामनेई की बंद मुट्ठी साम्राज्वाद के विरोध में ईरान का नया प्रतीक बनेगी?

(लेखक- तनवीर जाफरी)

पेंशन सत्यापन सरल, सुरक्षित व डिजिटल

सेवानिवृत्ति किसी भी सरकारी कर्मचारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। दशकों तक देश और समाज की सेवा करने के बाद पेंशन उसके सम्मानजनक जीवन का आधार बनती है। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन प्रमाणपत्र, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है और पेंशन का वास्तविक हकदार भी वही है।

वर्षों तक यह प्रक्रिया कागजी दस्तावेजों, कार्यालयों के चक्कर और लंबी कतारों तक सीमित रही, लेकिन डिजिटल तकनीक ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र सत्यापन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की है। इस बार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि चिकित्सकीय रूप से अक्षम पेंशनभोगियों को छोडकर सभी पेंशनभोगी एवं पारिवारिक पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे।

केवल वे पेंशनभोगी जो चिकित्सकीय रूप से अक्षम हैं, वे पूर्व की भांति संबंधित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित हस्ताक्षरित मैनुअल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि डिजिटल सुशासन की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी बल्कि सरकारी अभिलेखों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरूआत की थी। इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को हर वर्ष सरकारी कार्यालयों अथवा बैंक शाखाओं में जाकर हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अनिवार्यता से मुक्त करना था। आज यह प्रणाली देशभर में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और करोड़ों पेंशनभोगी इसका लाभ उठा रहे हैं। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से तैयार होने वाला यह डिजिटल प्रमाणपत्र सीधे संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण तक पहुंच जाता है। इससे न तो कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है और न ही बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में इस व्यवस्था का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राज्य के अनेक पेंशनभोगी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां जिला मुख्यालय या बैंक शाखा तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। बरसात, बर्फबारी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां भी कई बार आवागमन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में डिजिटल जीवन प्रमाण व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (कोषागार, लेखा एवं लॉटरी) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए अधिकृत संस्था के रूप में शामिल कर लिया है। इसका सीधा लाभ उन हजारों पेंशनभोगियों को मिलेगा जो अपने निकटतम डाकघर तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन बैंक अथवा कोषागार कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और डाक विभाग का देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तृत नेटवर्क है। हिमाचल प्रदेश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में डाकघर और ग्रामीण डाक सेवक उपलब्ध हैं।

अब पेंशनभोगी अपने निकटतम डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शाखा अथवा डाक कर्मी की सहायता से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करवा सकते हैं। कई स्थानों पर डाक कर्मी घर-घर जाकर भी यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वृद्ध और असहाय पेंशनभोगियों को विशेष राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक अधिकृत माध्यम निर्धारित किए हैं। अब जीवन प्रमाणपत्र जिला कोषागार कार्यालय, उप-कोषागार, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकघर अथवा स्वयं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे प्रत्येक पेंशनभोगी अपनी सुविधा और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकल्प चुन सकता है। डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पहले कई वरिष्ठ नागरिकों को केवल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण यह यात्रा उनके लिए अत्यंत कठिन होती थी। अब डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। प्रमाणपत्र तैयार होते ही उसका डिजिटल रिकॉर्ड संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंच जाता है, जिससे किसी प्रकार की देरी या दस्तावेज गुम होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है।

तकनीक के विकास के साथ अब फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो चुकी हैं। जिन पेंशनभोगियों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण कठिन हो जाता है, वे चेहरे की पहचान के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से अत्यधिक वृद्ध नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जिनके फिंगरप्रिंट समय के साथ स्पष्ट नहीं रह जाते। जीवन प्रमाणपत्र तैयार करवाने के लिए सामान्यत: आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, पीपीओ संख्या, बैंक खाते का विवरण तथा पेंशन वितरण संस्था से संबंधित जानकारी आवश्यक होती है। यदि आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो पूरी प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है। सरकार ने चिकित्सकीय रूप से अक्षम पेंशनभोगियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विशेष प्रावधान भी बनाए हैं। ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से बायोमेट्रिक अथवा डिजिटल प्रमाणीकरण कराना संभव नहीं है, वे संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र पूर्ववत प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को तकनीकी कारणों से परेशानी का सामना न करना पड़े। डिजिटल व्यवस्था सावधानी की भी अपेक्षा करती है।

उमा ठाकुर
स्वतंत्र लेखिका

आलेख

सात पुश्तों के लिए काली कमाई जोड़ कर बैठे हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी!

देश में भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी बन रहा है जिससे आम आदमी को रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के अनुसार, भारत 91वें स्थान पर है ।इस सूची में 182 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 100 में से 39 अंक मिले हैं। 0 अंक का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अंक का अर्थ पूर्णत: पारदर्शी या ईमानदार होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थिति में पिछली रैंकिंग के मुकाबले पांच स्थानों का सुधार हुआ है।

आपको बता दें कि देश के सिस्टम से जुड़े भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग कर जमा की गयी अकूत चल अचल संपत्ति का भंडार है। भारत में भ्रष्टाचारी अधिकारियों की धर-पकड़ और उनसे अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त (राजसात) करने के लिए बेहद कड़े कानूनी प्रावधान और सक्रिय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश विजिलेंस और कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा की गई बड़ी छापेमारी इस बात का जीवंत उदाहरण हैं, जहां भ्रष्ट अधिकारियों के गुप्त लॉकरों से करोड़ों रुपये नकद और किलो के हिसाब से सोना बरामद किया गया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग (विजिलेंस टीम) ने जुलाई 2026 में आगरा के पूर्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने उनके लखनऊ स्थित अलीगंज आवास पर छापेमारी कर करीब 35 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी जांच और कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की छापेमारी में उनके घर के कोने-कोने से भारी मात्रा में घर के विभिन्न हिस्सों में पैकेटों में छिपाकर रखे गए 1.62 करोड़ नकद मिले ।लगभग 13 किलोग्राम सोना और 9 किलोग्राम चांदी (बिस्किट, बार और आभूषण के रूप में) जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ आंकी गई है। लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी और रायबरेली में कई मकानों, भूखंडों (प्लॉट्स), फ्लैटों और कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 13 करोड़ के आसपास है ।बैंक खातों, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस स्कीमों में 1 करोड़ से अधिक के निवेश के दस्तावेज मिले। इसके अलावा दो लग्जरी कारें इनोवा और आइ20 और एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। 300 की घूस की शिकायत से खुला राज इस विशाल साम्राज्य का पदार्फाश साल 2020 में हुई एक छोटी सी शिकायत से शुरू हुआ था। ललित कुमार जब कानपुर में तैनात थे, तब उन पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 300 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। तत्कालीन परिवहन आयुक्त की अनुमति के बाद एंटी-करप्शन और विजिलेंस विभाग ने उनकी गोपनीय जांच शुरू की, जिससे उनकी आय से अधिक संपत्ति के इस बड़े मामले की परतें खुलती चली गईं। ललित कुमार अक्टूबर 2025 में आगरा से सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) हुए थे।

इस से छह दिन पूर्व 4 जुलाई को अकोला अकोला में हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किरण पुरुषोत्तम चौधरी सह-जिला निबंधक तथा मुद्रांक जिलाधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की' उनके खिलाफ 10,000 रिश्वत लेने का मामला दर्ज होने के बाद उनके जलगांव स्थित आवास पर छापेमारी की गई, जहां से 2.94 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति बरामद हुई है' किरण पुरुषोत्तम चौधरी, तत्कालीन अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार और स्टाम्प ड्यूटी अधिकारी (श्रेणी-क), अकोला महारा एसीबी ने उन्हें 26 जून को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था 'बरामद की गई जलगांव स्थित घर पर छापेमारी कर 1.53 करोड़ से अधिक नकद 60 लाख के सोने के बिस्किट व आभूषण तथा अन्य कीमती धातुएं' लगभग 62 लाख की बेनामी संपत्ति के कागजात 'लगभग 2.94 करोड़ 'यह जब्ती महाराष्ट्र के नासिक, अकोला और जलगांव की एसीबी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है'.

इसी सप्ताह तेलंगाना के हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संकीरेड्डी भीम रेड्डी को लगभग 300 करोड़ की अवैध बेनामी संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने अधिकारी के तेलंगाना और कर्नाटक स्थित कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। शुरूआती जांच में करीब 300 करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। अधिकारी के ठिकानों से 2 किलोग्राम सोने के आभूषण और 20 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान उनके घर से 3.60 लाख और एक अन्य ठिकाने से 40 लाख कैश मिला। रिश्तेदारों और बेनामियों के नाम पर 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, व्यावसायिक भूखंड, कई लग्जरी फ्लैट और आलीशान विला के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। उनके बैंक खातों में लगभग 19.91 लाख जमा पाए गए हैं। भ्रष्ट आचरण और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद एसीबी कोर्ट ने आरोपी डीएसपी भीम रेड्डी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल भेज दिया है।

25 फरवरी 2026 तीस हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए खनन विभाग के उप निदेशक देवव्रत महांति की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है ।भुवनेश्वर स्थित उनके फ्लैट से 4 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई ।इसके अलावा, महांति के कार्यालय की दराज और उनके पास से 1.20 लाख रुपये नकद भुवनेश्वर के पहाल क्षेत्र में लगभग 2400 वर्गफुट में बना एक भव्य दो मंजिला मकान, करीब 130 ग्राम सोना जब्त किया है।

उधर 9 जून 2026 भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ जे. मोहन नाइक और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कई प्रॉपर्टीज पर एक साथ छापे मारे। उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है।

यह तलाशी हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों सहित लगभग 15 जगहों पर की गई। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान अधिकारियों को सोने के बिस्किट, गहने, चांदी की चीजें, कैश और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। शुरूआती अनुमानों के अनुसार, जांच के दायरे में आई कुल संपत्ति की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है।

ये तो सिर्फ बानगी नमूना भर है देश भर में करीब एक सौ सरकारी कर्मचारी अधिकारीयों के कब्जे से आय से अधिक जुटाई गयी करोड़ों अरबों की संपति मिल रही है। एक एक अधिकारी ने सौ से तीन चार सौ करोड़ तक की अवैध संपत्ति जुटाने का काम किया है जिस से पता चल जाता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है।

केन्द्र में भारतीय जनतापार्टी की सरकार केन्द्र और विभिन्न प्रदेशों में आयी, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस का नारा तो रहा लेकिन स्थितियों में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। इसके लिए सब कुछ डिजिटल आनलाइन करने की कवायद हुई वह चाहे टेंडर हो या अन्य जनउपयोगी सुविधाएं लेकिन राजस्व से लेकर कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। डबल इंजन की सरकार भी इससे मुक्त नहीं कर पायी है। भ्रष्टाचार के बारे जारी होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 182 देशों की रिपोर्ट में भारत 91 वें स्थान पर है। यह संस्था सरकार संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करती है और उसके आधार पर रैंकिंग तय करती है ।यदि इस रैंक को न भी मानें तो भी आम आदमी से लेकर खास आदमी तक इससे प्रभावित है ।सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार समाप्त होने के बजाय निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में अब इसे रिश्वत , घूस के बजाय सुविधाशुल्क और प्रथा के रूप में अपनाया जा चुका हैं। सिर्फ जीरो टालरेंस का नारा देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। निचले स्तर से लेकर उच्चस्तर पर कदम पर भ्रष्टाचार की विषबेल फैल रही हैं। पिछले दिनों एक हाइकोर्ट जज के आवास के कमरे में आग लगने पर नोटों से भरे बोरों का जलते देखा जाना और उस पर सटीक कारवाई नहीं किया जाने से पता चल जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार और यहां तक कि न्यायपालिका भी पर्याप्त गंभीर नहीं है। जाहिर है कि देश की उन्नति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है सरकार को गंभीरता से सख्त कदम उठाने चाहिए और आम चुनाव का मुद्दा भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग ही होना चाहिए क्योंकि पुलिस पटवारी से लेकर ऊंची न्याय की कुर्सियों तक भ्रष्टाचार की जड़ें देश को खोखला कर रहीं हैं और देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहीं हैं।

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 39 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

डीयू ने पीजी दाखिले की तीसरी सूची के तहत 15 तक जमा करें फीस

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सीएसएएस (पीजी) 2026-27 के तहत तीसरे आवंटन दौर का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। विश्वविद्यालय ने बताया कि सीडब्ल्यू, खेल और वार्ड सुपरन्यूमेरेरी कोटा के आवंटन में देरी के कारण प्रवेश कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विभागीय केंद्र और कॉलेज 14 जुलाई रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करेंगे।

ज्ञात हो कि तीसरे दौर में सीट आवंटित होने वाले अभ्यर्थी 13 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर चुके थे। यह संशोधित कार्यक्रम प्रदर्शन-आधारित पाठ्यक्रमों जैसे एमएफए, एमए म्यूजिक, बीपीएड और एमपीएड के साथ-साथ सीडब्ल्यू, खेल और वार्ड सुपरन्यूमेरेरी कोटा के अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा।विश्वविद्यालय ने कहा है कि यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो आवश्यकता के अनुसार आगे भी आवंटन के अतिरिक्त दौर घोषित किए जा सकते हैं।

जेएनयू में सेमेस्टर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

नईदिल्ली, 13 जुलाई(वेब वार्ता)।जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) ने सोमवार को मूल्यांकन शाखा को ज्ञापन सौंपकर सेमेस्टर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। छात्रसंघ का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि भुगतान पोर्टल पर सर्वर की धीमी गति के कारण कई छात्र फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, अनेक छात्रों को अभी तक मेरिट-कम-मीन्स (एमसीएम) छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।जेएनयूएसयू ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं को देखते हुए सेमेस्टर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि सभी छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें।

दिल्ली लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन से होगी शुरू, हर माह मिलेंगे 2500

नई दिल्ली, 13 जुलाई(वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ कर सकती है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी।

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। अनुमान है कि राजधानी की लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का वादा किया था और अब सरकार इसके क्रियान्वयन की दिशा में अंतिम तैयारियां कर रही है।

लाल किला विस्फोटः मृतकों के अंतिम संस्कार को अदालत की अनुमति

नई दिल्ली, 13 जुलाई(वेब वार्ता)। दिल्ली की विशेष अदालत ने लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट में मृत 11 लोगों के शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है। अदालत ने विस्फोट में मारे गए वाहन चालक डॉ. उमर उन नबी के शरीर के अवशेषों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार दफनाने की मंजूरी प्रदान की है। विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने निर्देश दिया कि सभी मृतकों के शरीर के अवशेषों का सम्मानपूर्वक और उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अंतिम संस्कार किया जाए। साथ ही जांच एजेंसी से इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने अदालत को बताया कि सभी आवश्यक न्यायालयिक विज्ञान संबंधी प्रमाण एकत्र किए जा चुके हैं।एजेंसी ने यह भी कहा कि लंबे समय से सुरक्षित रखे गए शरीर के अवशेष खराब होने लगे थे, इसलिए उनके अंतिम निपटान की अनुमति आवश्यक थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच अभिकरण इस विस्फोट मामले में पहले ही विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत कर चुका है। हाल ही में तीन और आरोपितों के विरुद्ध अनुपूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया, जिसके बाद इस प्रकरण में आरोपितों की कुल संख्या 13 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने मॉडल टाउन में मिशन 70 लाख पौधा रोपण महाअभियान में लिया हिस्सा

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मॉडल टाउन में आयोजित एक पेड़ मां के नाम- मिशन 70 लाख पौधा रोपण महाअभियान में हिस्सा लेकर पौधा रोपण किया। इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1,100 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अशोक गोयल, बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि और अन्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जुलाई को मेगा प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पोर्टल- https://greendrive.delhivanmahotsav.in भी शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को पौधारोपण अभियान से जुड़ने और अपनी सुविधानुसार तिथि, समय और स्थान का चयन कर स्लॉट बुक करने की सुविधा दी गई है। दिल्ली सरकार वृक्ष रथ के माध्यम से आपके घर नि:शुल्क पौधे पहुंचाएगी। साथ ही नागरिक नर्सरी लोकेटर के माध्यम से अपनी निकटतम सरकारी नर्सरी का चयन कर वहां से नि:शुल्क पौधा भी प्राप्त कर सकते हैं।

...अपना योगदान दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के प्रत्येक खाली और उपयुक्त स्थान को हरित क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।इसी क्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में सेंट्रल वर्ज, मेट्रो कॉरिडोर के नीचे और सड़कों के दोनों ओर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ह्यएक पेड़ मां के नामह्ल अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मातृत्व के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक जनआंदोलन है। यह अभियान नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहा है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें और दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

द्वारका में जिला स्तरीय कमेटी बैठक में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा की हुई समीक्षा

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को द्वारका स्थित डीसीपी कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में सहभागिता की। बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित एवं सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बैठक में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच निरंतर समन्वय के माध्यम से जनमानस की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने, नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा सुशासन एवं जनसेवा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।

कारापुर गांव के आंदोलन को आम आदमी पार्टी का समर्थन

सीजेपी से मिले आप विधायक

नई दिल्ली, वेब वार्ता

गोवा के कारापुर गांव के लोग बिल्डर माफिया के खिलाफ पिछले 100 दिनों से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने सोमवार को इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी की गोवा प्रभारी आतिशी आंदोलन में शामिल हुईं और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताई। इस दौरान बुराड़ी से विधायक संजीव झा, दिल्ली की पूर्व महापौर डॉ. शैली ओबरॉय, एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग, विधायक कुलदीप कुमार तथा पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर आतिशी ने कहा कि कारापुर गांव के लोग पिछले 100 दिनों से अपने गांव और जमीन को एक बड़े प्रोजेक्ट से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ग्रामीणों के बजाय बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स का साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कारापुर के लोग अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि कारापुर गांव के लोगों का यह संघर्ष केवल एक गांव का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का संघर्ष है जो अपनी जमीन, अधिकार और न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा आम जनता के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी अन्याय के खिलाफ हर संघर्ष में मजबूती से साथ निभाएगी। कारापुर गांव के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पार्टी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने और ग्रामीणों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया। आतिशी ने कहा कि जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिली, जहां उनका अनशन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी सेहत बिगड़ रही है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वे देश के युवाओं के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आतिशी ने सोनम वांगचुक और युवा 'कॉकरोचेस' को आगे बढ़ने की शक्ति और शुभकामनाएं दी।

एसआईआर प्रपत्र भरवाने के लिए शिविर आयोजित, लोगों को मिली सुविधा

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)

ईस्ट गोरख पार्क आरडब्ल्यूए सुपर वेलफेयर काउंसिल की ओर से एसआईआर प्रपत्र भरवाने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। काउंसिल के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि प्रपत्र भरने में लोगों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया।

संजीव शर्मा ने बताया कि शिविर में क्षेत्र के सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता मिल सकी। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने अपने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रपत्र भरकर वहीं जमा भी कराए।

उन्होंने कहा कि कार्यदिवसों में बूथ स्तरीय अधिकारियों को घर-घर जाकर सभी सदस्यों से मिलना कठिन हो रहा था। इसी कारण अधिक से अधिक लोगों की सुविधा के लिए रविवार को शिविर आयोजित किया गया, जिससे बेहतर सहभागिता सुनिश्चित हो सकी। संजीव शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान लोगों की शंकाओं का समाधान किया गया और प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को लेकर व्याप्त भ्रम भी दूर हुआ। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि शेष लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने शिविर की सफलता के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

उस्मानपुर और गढ़ी मेंडू को ओ जोन से मुक्त किया जाएः भीष्म शर्मा

नई दिल्ली, वेब वार्ता। पूर्व विधायक भीष्म शर्मा ने यमुनापार के ऐतिहासिक गांव उस्मानपुर और गढ़ी मेंडू को ओ जोन से मुक्त करने की मांग करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में लगाए गए नोटिसों से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों गांवों के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। भीष्म शर्मा ने कहा कि यदि इन क्षेत्रों में मजबूत और स्थायी बांध का निर्माण कराया जाए तो बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। उनका कहना था कि इससे दोनों गांवों को ओ जोन से मुक्त करने का रास्ता भी आसान होगा। उन्होंने दावा किया कि विधायक रहते हुए उन्होंने उस्मानपुर में बांध निर्माण का कार्य शुरू कराया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका।

जलभराव रोकने में सरकार विफल रहीः अरुण तोमर

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के घोंडा विधानसभा के पूर्व संगठन मंत्री अरुण तोमर ने दावा किया कि मानसून की पहली भारी बारिश ने दिल्ली सरकार की जलभराव रोकने संबंधी तैयारियों की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित नहीं हुईं।

अरुण तोमर ने कहा कि बारिश के बाद राजधानी के कई क्षेत्रों में जलभराव, टूटी सड़कें और गाद जमा होने की समस्या देखने को मिली, जिससे लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर दोपहिया वाहन चालकों को अपने वाहन धक्का देकर निकालने पड़े, जबकि पैदल चलने वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने जलभराव रोकने के बड़े दावे किए थे, लेकिन पहली ही बारिश में व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ गई। उनका कहना था कि राजधानी में विभिन्न स्थानों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। अरुण तोमर ने कहा कि अब जबकि दिल्ली और दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे जलभराव की समस्या और उससे हुई परेशानियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

यमुना खादर में फिर बसीं हजारों झुग्गियां, बाढ़ से पहले बढ़ी प्रशासन की चिंता

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बावजूद एक बार फिर बड़ी संख्या में झुग्गियां बस जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अनुमान है कि खादर क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। आगामी दिनों में यमुना के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रशासन को राहत एवं अस्थायी शिविरों की तैयारी करनी पड़ रही है, जिस पर हर वर्ष लाखों रुपये का व्यय होता है।

गत वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार तथा पुराने लोहे के पुल के निकट स्थित अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया था। इसके बावजूद खादर क्षेत्र में दोबारा बड़ी संख्या में लोगों के बस जाने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत से दोबारा झुग्गियां खड़ी कर ली हैं।

मयूर विहार, पुराने लोहे के पुल, कश्मीरी गेट, उस्मानपुर, सिग्नेचर पुल तथा बदरपुर खादर गांव के आसपास यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना है कि अतिक्रमण के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है और जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार खादर क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इनमें से कई परिवार सब्जी एवं फल विक्रय, कपड़ों की फेरी तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे इन झुग्गियों में किराया देकर रह रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि यदि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचता है तो खादर क्षेत्र को तत्काल खाली कराया जाएगा। इसके लिए अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। स्थायी समाधान के लिए प्रभावी निगरानी, दोबारा अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की ठोस नीति आवश्यक है। अन्यथा हर वर्ष बाढ़ के मौसम में प्रशासन को राहत कार्यों पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और यमुना खादर में अवैध बसावट का सिलसिला जारी रहेगा।

देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगीः एम.एल. भास्कर

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे जनता का विश्वास पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है।

एम. एल. भास्कर ने कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, श्रमिक, कर्मचारी, व्यापारी और अन्य वर्ग कांग्रेस की नीतियों तथा जनहित के लिए किए जा रहे प्रयासों से प्रभावित होकर दोबारा पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी।

दिल्ली में पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप, फरार कॉन्स्टेबल की तलाश तेज

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली में एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले ने सनसनी फैला दी है। पूर्वी जिला पुलिस की वाहन चोरी निरोधक शाखा में तैनात कॉन्स्टेबल मनीष भाटी पर अपनी पत्नी प्रियंका भाटी की हत्या का आरोप है। घटना सोमवार तड़के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के निकट हुई। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया, जबकि पूरी घटना आसपास लगे निगरानी चित्रांकन यंत्रों में कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार मनीष भाटी और प्रियंका भाटी की शादी लगभग 3 वर्ष पहले हुई थी और दोनों पूर्वी विनोद नगर क्षेत्र में रहते थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोमवार तड़के दोनों एक दोपहिया वाहन से घर से निकले थे। अस्पताल के समीप किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद प्रियंका को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल महिला को एक वाहन चालक तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे निगरानी चित्रांकन यंत्रों की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस दल गठित किए गए हैं तथा मामले के प्रत्येक पहलू की गहन जांच की जा रही है।

इस घटना के बाद लगभग 2 वर्ष पहले दर्ज कराई गई प्रियंका की शिकायत भी चर्चा में आ गई है। शिकायत में उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही नकद धनराशि और कार की मांग की जाने लगी थी तथा मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। प्रियंका ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि उनके पति का किसी अन्य महिला से संबंध था। उन्होंने दावा किया था कि इस विषय पर आपत्ति जताने पर उनके साथ मारपीट की गई और कई बार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि पति कथित रूप से दूसरी शादी करना चाहता था और इसी कारण उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला ने पुलिस को दिए अपने पूर्व बयान में यह भी आरोप लगाया था कि कई अवसरों पर उनके माथे पर अवैध हथियार रखकर धमकाया गया।

सिख समाज की एकता पर जोर, एनसीआर सम्मेलन में हजारों लोगों की भागीदारी

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। एनसीआर गुरुद्वारा फाउंडेशन की ओर से गाजियाबाद के वसुंधरा में आयोजित विशाल सिख सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में सिख समाज की एकता, पंथ की उन्नति, शिक्षा और सामाजिक सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरदार हरमीत सिंह कालका और सरदार जगदीप सिंह कहलों ने कहा कि सिख समाज को एकजुट होकर पंथ की चढ़दी कला और सामाजिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीआर गुरुद्वारा फाउंडेशन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के सिख समाज को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कई पहल कर रही है। गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही, एनसीआर के सिख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन देने की योजनाओं की भी घोषणा की गई।

सम्मेलन में पंथक एकता को समय की आवश्यकता बताते हुए समाज के सभी वर्गों से सहयोग और समन्वय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इस दौरान एनसीआर के विभिन्न शहरों के लिए नए संयोजकों की घोषणा भी की गई, जो स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति के सदस्यों और सहयोगियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई तथा समाज को एकजुट करने के प्रयासों की सराहना की गई।

दिल्ली पुलिस ने विफल की कारोबारी की हत्या की साजिश, दो शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में जबरन धन उगाही और सुनियोजित हत्याओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी जिला पुलिस की विशेष दल ने कुख्यात अपराधी हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह से जुड़े दो शूटरों को गिरफ्तार कर रोहिणी क्षेत्र के एक प्रमुख कारोबारी की हत्या की साजिश को समय रहते विफल कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि-विवादित किशोर भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध अर्धस्वचालित पिस्तौल तथा छह जीवित कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार विदेश में रहकर गिरोह का संचालन कर रहे हिमांशु उर्फ भाऊ ने मार्च माह में रोहिणी के एक प्रतिष्ठित कारोबारी से बड़ी रकम की रंगदारी मांगी थी। इस संबंध में अमन विहार थाने में मामला दर्ज किया गया था। धमकी मिलने के बाद कारोबारी को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसी कारोबारी की हत्या के उद्देश्य से गिरोह के स्थानीय सहयोगियों ने दोनों शूटरों को हथियार उपलब्ध कराकर हरियाणा से दिल्ली भेजा था।

उत्तरी जिला की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि विशेष दल को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य नेहरू विहार क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और वहां से रोहिणी जाकर वारदात को अंजाम देंगे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 6 और 7 जुलाई की मध्यरात्रि दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। इसके बाद तिमारपुर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के मनोहरपुर गांव निवासी प्रदीप उर्फ काली (26) तथा फतेहाबाद जिले के एक किशोर के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि प्रदीप पहले बस परिचालक का कार्य करता था और बाद में एक मदिरा विक्रय केंद्र पर कार्यरत था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि किशोर आरोपी अपने एक परिचित के माध्यम से हिमांशु उर्फ भाऊ के संपर्क में आया था। उसे दूरभाष के माध्यम से दिल्ली में एक बड़े कारोबारी की हत्या करने का निर्देश दिया गया। यात्रा के दौरान गिरोह के विभिन्न सहयोगियों ने अलग-अलग स्थानों पर दोनों आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराए तथा लगातार उनके ठहरने और आने-जाने की व्यवस्था करते रहे। जांच के अनुसार आरोपियों को हरियाणा से अलग-अलग वाहनों के माध्यम से दिल्ली लाया गया। उन्हें नेहरू विहार क्षेत्र में अन्य सहयोगियों से मिलने और आगे की योजना के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी साजिश को विफल कर दिया।

उपनिरीक्षक ने सरकारी पिस्तौल से जान दी, जांच शुरू

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाने में तैनात उपनिरीक्षक सोमेश मीणा ने सोमवार को पुलिस बैरक में अपनी सरकारी पिस्तौल से स्वयं को गोली मार ली। गंभीर अवस्था में उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उपनिरीक्षक को घायल अवस्था में पाया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और न्यायालयिक विज्ञान दल भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या घटनास्थल से कोई पत्र या अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक परिस्थितियों और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों पर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

संक्षिप्त वार्ता

पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। स्वामी विवेकानंद सभागार में सोमवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला सैनिक बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को प्रत्येक थाने में पूर्व सैनिकों के लिए अलग शिकायत रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए, ताकि उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजस्व, पुलिस, समाज कल्याण, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में भूमि संबंधी विवाद, पेंशन, पारिवारिक लाभ, रोजगार, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत की तथा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

युवा नेता संचित अग्रवाल ने नौनिहालों संग किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

वेब वार्ता/हरदोई

वृहद पौधारोपण अभियान के तहत सन शाइन स्कूल, कछौना में युवा नेता संचित अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। संचित अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "एक पेड़ मां के नाम" पहल ने पौधारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पौधे का संरक्षण और संवर्धन भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि सभी लोग एक-एक पौधे की देखभाल का संकल्प लें, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। कार्यक्रम में सन शाइन स्कूल के प्रबंधक सुनील सोनी, प्रधानाचार्य शोएब, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय शुक्ला, अजय बाजपेई, व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि गुप्ता, राहुल अग्रवाल, एकता मंच के संयोजक दरोगा सिंह, महामंत्री अवधेश गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना हमारी प्राथमिकता: नितिन गडकरी

बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई गति: मुख्यमंत्री

लखनऊ, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर सहमति बनी।

बैठक में नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। ऐसे में राज्य में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिताओं के स्थानांतरण तथा अन्य विभागीय औपचारिकताओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर सभी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण के साथ सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर समान रूप से ध्यान देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश, उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, जबकि 9,329 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर अब तक लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ही लगभग 23,445 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। समीक्षा के दौरान मथुरा-बरेली-सितारगंज, आगरा-अलीगढ़, आगरा-ग्वालियर-झांसी-नागपुर आर्थिक गलियारा, कानपुर रिंग रोड, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना तथा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सोनौली-गोरखपुर, गाजीपुर-बलिया-बिहार सीमा, प्रयागराज दक्षिणी रिंग रोड तथा प्रयागराज-जौनपुर-आजमगढ़-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनके पूरा होने से भारत-नेपाल सीमा, बौद्ध पर्यटन परिपथ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, करें सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी ने किया 'जनता दर्शन', हर पीड़ित की समस्या सुन समाधान के लिए दिए निर्देश

लखनऊ, वेब वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे।

अपराध व अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में की जाय शीघ्रता

मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये। पीड़ितों ने आरोपितों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को ससमय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाय।

बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे लोग, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी 'जनता दर्शन' के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची। पीड़ितों ने बताया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट कई लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू को मिला जीवनरक्षक कवच

वेब वार्ता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉ. मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू को एक बड़ी सौगात मिली है। शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी एस.पी. मल्होत्रा ने दरियादिली दिखाते हुए अस्पताल को एक अत्याधुनिक बीपीएल डीएफ-2509 डिफिब्रिलेटर मशीन दान की है। यह उपकरण हृदय और श्वसन संबंधी आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान बचाने में बेहद मददगार साबित होगा।

नई डिफिब्रिलेटर मशीन की मुख्य विशेषताएं

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, यह नई मशीन आईसीयू के क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट को एक नए स्तर पर ले जाएगी। इसकी खासियतें निम्नलिखित हैं। यह मशीन गंभीर मरीज के हृदय की गतिविधियों पर लगातार और सटीक नजर रखती है। मोनोफेसिक इलेक्ट्रिक शॉक आपातकालीन स्थिति में दिल की धड़कन रुकने या अनियमित होने पर यह 2 से 360 जूल तक का मोनोफेसिक इलेक्ट्रिक शॉक देने में सक्षम है। इसके साथ ही इन-बिल्ड प्रिंटर इलाज के दौरान मरीज के हार्ट ग्राफ और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक इन-बिल्ड प्रिंटर भी लगाया गया है, जिससे डॉक्टरों को त्वरित फैसले लेने में मदद मिलेगी।

चेस्ट हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अवधेश कुमार ने समाजसेवी एस.पी. मल्होत्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग विशेष रूप से उन गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। जब समाज के जागरूक नागरिक इस तरह आगे आते हैं, तो सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिलती है।

एक पेड़ माँ के नाम से परिवहन विभाग ने किया महा-वृक्षारोपण

वेब वार्ता, कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कानपुर के परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। संभागीय परिवहन अधिकारियों और आरआई ने विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों, फिटनेस सेंटरों और स्टेक होल्डर्स परिसरों में वृहद वृक्षारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत संदेश दिया है। शासन द्वारा निर्धारित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। जिसके क्रम में अभियान को व्यापक रूप देने के लिए परिवहन विभाग से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स परिसरों को चुना गया, जिनमें मुख्य रूप से एटीएस, एडीटीटी, ड्राइविंग स्कूल व आई एंड सी फिटनेस सेंटर शामिल है। इस बेहद खास मौके पर आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही हमारे जीवन का असली आधार है। हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण हमेशा मुस्कुराता रहे, तो हर नागरिक को वृक्षारोपण करना ही होगा। अभियान में प्रमुख रूप से आर.आर. सोनी (उप परिवहन आयुक्त), राकेन्द्र कुमार सिंह (आरटीओ प्रशासन), राहुल श्रीवास्तव (आरटीओ प्रवर्तन), आलोक कुमार सिंह (एआरटीओ प्रशासन), कहकशां खातून (एआरटीओ प्रवर्तन), सोमलता यादव (एआरटीओ प्रवर्तन), विंध्यांचल गुप्ता (एआरटीओ), संतोष कुमार (आरआई) समेत समस्त पीटीओ और विभागीय स्टाफ मौजूद रहा।

डीवी/पीएसटी प्रक्रिया का एसपी ने निरीक्षण कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत जनपद हरदोई में चल रही दस्तावेज सत्यापन (डीवी) एवं शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) प्रक्रिया का सोमवार को पुलिस अधीक्षक हरदोई तथा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का बारीकी से जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही, प्रतीक्षा स्थल, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई जाए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ निर्वहन करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने अभ्यर्थियों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित होने की सलाह दी।

निरीक्षण के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया।

चकरोड की पैमाइश के दौरान बुजुर्ग की मौत

हत्या के आरोप और पुलिस के दावों में विरोधाभास; जांच जारी

वेबवार्ता/हरदोई। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के ईसेपुर गांव में सरकारी चकरोड की पैमाइश के दौरान 72 वर्षीय राजेंद्र पुत्र नेकराम की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। घटना को लेकर मृतक पक्ष और पुलिस के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है। एक ओर परिजन और ग्रामीण इसे लोहे की रॉड से किए गए हमले में हुई हत्या बता रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौके पर किसी प्रकार की मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। अब पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मृतक की फाईल फोटो

जानकारी के अनुसार, ईसेपुर गांव में सरकारी चकरोड को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। आवेदक अभिनय पुत्र रामपाल की शिकायत पर रविवार को राजस्व विभाग की टीम लेखपाल और कानूनगो के साथ मौके पर पैमाइश करने पहुंची थी। मृतक पक्ष का आरोप है कि पैमाइश पूरी होने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और राजेंद्र पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गुड्डू यादव, धीरेंद्र, पप्पू यादव, शैलेंद्र, आकाश यादव, अनुपम यादव और अमिताभ यादव समेत कई लोगों पर हमले का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर हरदोई पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्व टीम शिकायत की जांच और पैमाइश कर रही थी। निरीक्षण के बाद राजेंद्र पुत्र नेकराम अचानक अज्ञात कारणों से अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी हरपालपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा राजस्व टीम से पूछताछ में अब तक किसी भी प्रकार के झगड़े या मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस मामले में परिजनों के हत्या के आरोप और पुलिस की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष आमने-सामने हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के निष्कर्ष ही यह तय करेंगे कि बुजुर्ग की मौत हमले के कारण हुई या किसी अन्य वजह से।

मानसिक रोगियों के अधिकार और नशामुक्ति पर शाहाबाद में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

वेब वार्ता/हरदोई

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेशों के क्रम में सोमवार को तहसील शाहाबाद के उधरनपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर में मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उससे बचाव विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश माननीय रीता कौशिक एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/प्रभारी श्रीमती स्मिता गोस्वामी के निर्देशन तथा तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद की सचिव/तहसीलदार श्रीमती संध्या यादव के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

शिविर की अध्यक्षता काउंसिलर शिवानी तिवारी ने की। उन्होंने उपस्थित बच्चों एवं ग्रामीणों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया तथा शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी।

वहीं लीगल एड क्लीनिक के राघवेंद्र विक्रम सिंह ने मानसिक एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और उन्हें उपलब्ध स्वास्थ्य एवं कानूनी सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में गरिमा और समानता के साथ जीवन जीने, बिना भेदभाव के अवसर प्राप्त करने, उचित स्वास्थ्य सेवाएं लेने तथा निःशुल्क विधिक सहायता पाने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने बताया कि ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39अ तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में सुरक्षित हैं।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि मानसिक या बौद्धिक अक्षमता किसी व्यक्ति को समाज से अलग नहीं करती, बल्कि वह समाज का समान अधिकारों वाला सदस्य है। साथ ही नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी, ग्रामीण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

'एक पेड़ मां के नाम' वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत तुलसी पार्क में लगाए गए पौधे

भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने किया नेतृत्व

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। एक पेड़ मां के नाम' वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुलसी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित वातावरण के निर्माण तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का संदेश देते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह अपनी मां के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायी जनआंदोलन है। उन्होंने सभी कार्यकताओं एवं नागरिकों से अपील की कि वे अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लें। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण समय की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे,तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री बिंदु विश्वकर्मा,जिला मीडिया प्रभारी डी.पी.सिंह 'बैस',राजाराम गौतम,संदीप उपाध्याय,अंशुमाली भारतवंशी,आलोक पांडेय,सौरभ तुलस्यान,हिमांशु शुक्ला सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी कार्यकताओं ने लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में हरदोई ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि

लक्ष्मीकान्त पाठक। वेबवार्ता

हरदोई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में हरदोई ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 की प्रगति के आधार पर विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जनपद ने प्रदेश के शीर्ष-10 जिलों में स्थान बनाया है। यह जानकारी सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में दी गई। अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय सभी विभागों के बेहतर समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न विभागों की प्रगति, जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति, विकास कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा जनशिकायतों की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिन विभागों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई, उन्हें तत्काल सुधार करते हुए जुलाई माह के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि किसी भी योजना में लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक विभाग को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना होगा।

प्रदेश के टॉप-10 जिलों में बनाया स्थान

संक्षिप्त वार्ता

पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। स्वामी विवेकानंद सभागार में सोमवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला सैनिक बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को प्रत्येक थाने में पूर्व सैनिकों के लिए अलग शिकायत रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए, ताकि उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजस्व, पुलिस, समाज कल्याण, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में भूमि संबंधी विवाद, पेंशन, पारिवारिक लाभ, रोजगार, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत की तथा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

युवा नेता संचित अग्रवाल ने नौनिहालों संग किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

वेब वार्ता/हरदोई

वृहद पौधारोपण अभियान के तहत सन शाइन स्कूल, कछौना में युवा नेता संचित अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। संचित अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "एक पेड़ मां के नाम" पहल ने पौधारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पौधे का संरक्षण और संवर्धन भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि सभी लोग एक-एक पौधे की देखभाल का संकल्प लें, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। कार्यक्रम में सन शाइन स्कूल के प्रबंधक सुनील सोनी, प्रधानाचार्य शोएब, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय शुक्ला, अजय बाजपेई, व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि गुप्ता, राहुल अग्रवाल, एकता मंच के संयोजक दरोगा सिंह, महामंत्री अवधेश गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना हमारी प्राथमिकता: नितिन गडकरी

बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई गति: मुख्यमंत्री

लखनऊ, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर सहमति बनी।

बैठक में नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। ऐसे में राज्य में विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिताओं के स्थानांतरण तथा अन्य विभागीय औपचारिकताओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर सभी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण के साथ सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर समान रूप से ध्यान देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश, उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, जबकि 9,329 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर अब तक लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ही लगभग 23,445 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। समीक्षा के दौरान मथुरा-बरेली-सितारगंज, आगरा-अलीगढ़, आगरा-ग्वालियर-झांसी-नागपुर आर्थिक गलियारा, कानपुर रिंग रोड, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना तथा मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि सोनौली-गोरखपुर, गाजीपुर-बलिया-बिहार सीमा, प्रयागराज दक्षिणी रिंग रोड तथा प्रयागराज-जौनपुर-आजमगढ़-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनके पूरा होने से भारत-नेपाल सीमा, बौद्ध पर्यटन परिपथ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, करें सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी ने किया 'जनता दर्शन', हर पीड़ित की समस्या सुन समाधान के लिए दिए निर्देश

लखनऊ, वेब वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे।

अपराध व अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में की जाय शीघ्रता

मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये। पीड़ितों ने आरोपितों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को ससमय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाय।

बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे लोग, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी 'जनता दर्शन' के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची। पीड़ितों ने बताया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट कई लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू को मिला जीवनरक्षक कवच

वेब वार्ता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉ. मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू को एक बड़ी सौगात मिली है। शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी एस.पी. मल्होत्रा ने दरियादिली दिखाते हुए अस्पताल को एक अत्याधुनिक बीपीएल डीएफ-2509 डिफिब्रिलेटर मशीन दान की है। यह उपकरण हृदय और श्वसन संबंधी आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान बचाने में बेहद मददगार साबित होगा।

नई डिफिब्रिलेटर मशीन की मुख्य विशेषताएं

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, यह नई मशीन आईसीयू के क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट को एक नए स्तर पर ले जाएगी। इसकी खासियतें निम्नलिखित हैं। यह मशीन गंभीर मरीज के हृदय की गतिविधियों पर लगातार और सटीक नजर रखती है। मोनोफेसिक इलेक्ट्रिक शॉक आपातकालीन स्थिति में दिल की धड़कन रुकने या अनियमित होने पर यह 2 से 360 जूल तक का मोनोफेसिक इलेक्ट्रिक शॉक देने में सक्षम है। इसके साथ ही इन-बिल्ड प्रिंटर इलाज के दौरान मरीज के हार्ट ग्राफ और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक इन-बिल्ड प्रिंटर भी लगाया गया है, जिससे डॉक्टरों को त्वरित फैसले लेने में मदद मिलेगी।

चेस्ट हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अवधेश कुमार ने समाजसेवी एस.पी. मल्होत्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग विशेष रूप से उन गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। जब समाज के जागरूक नागरिक इस तरह आगे आते हैं, तो सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिलती है।

एक पेड़ माँ के नाम से परिवहन विभाग ने किया महा-वृक्षारोपण

वेब वार्ता, कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कानपुर के परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। संभागीय परिवहन अधिकारियों और आरआई ने विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों, फिटनेस सेंटरों और स्टेक होल्डर्स परिसरों में वृहद वृक्षारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत संदेश दिया है। शासन द्वारा निर्धारित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। जिसके क्रम में अभियान को व्यापक रूप देने के लिए परिवहन विभाग से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स परिसरों को चुना गया, जिनमें मुख्य रूप से एटीएस, एडीटीटी, ड्राइविंग स्कूल व आई एंड सी फिटनेस सेंटर शामिल है। इस बेहद खास मौके पर आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही हमारे जीवन का असली आधार है। हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण हमेशा मुस्कुराता रहे, तो हर नागरिक को वृक्षारोपण करना ही होगा। अभियान में प्रमुख रूप से आर.आर. सोनी (उप परिवहन आयुक्त), राकेन्द्र कुमार सिंह (आरटीओ प्रशासन), राहुल श्रीवास्तव (आरटीओ प्रवर्तन), आलोक कुमार सिंह (एआरटीओ प्रशासन), कहकशां खातून (एआरटीओ प्रवर्तन), सोमलता यादव (एआरटीओ प्रवर्तन), विंध्यांचल गुप्ता (एआरटीओ), संतोष कुमार (आरआई) समेत समस्त पीटीओ और विभागीय स्टाफ मौजूद रहा।

डीवी/पीएसटी प्रक्रिया का एसपी ने निरीक्षण कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत जनपद हरदोई में चल रही दस्तावेज सत्यापन (डीवी) एवं शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) प्रक्रिया का सोमवार को पुलिस अधीक्षक हरदोई तथा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का बारीकी से जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही, प्रतीक्षा स्थल, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई जाए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ निर्वहन करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने अभ्यर्थियों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित होने की सलाह दी।

निरीक्षण के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया।

चकरोड की पैमाइश के दौरान बुजुर्ग की मौत

हत्या के आरोप और पुलिस के दावों में विरोधाभास; जांच जारी

वेबवार्ता/हरदोई। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के ईसेपुर गांव में सरकारी चकरोड की पैमाइश के दौरान 72 वर्षीय राजेंद्र पुत्र नेकराम की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। घटना को लेकर मृतक पक्ष और पुलिस के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है। एक ओर परिजन और ग्रामीण इसे लोहे की रॉड से किए गए हमले में हुई हत्या बता रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौके पर किसी प्रकार की मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। अब पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मृतक की फाइल फोटो

जानकारी के अनुसार, ईसेपुर गांव में सरकारी चकरोड को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। आवेदक अभिनय पुत्र रामपाल की शिकायत पर रविवार को राजस्व विभाग की टीम लेखपाल और कानूनगो के साथ मौके पर पैमाइश करने पहुंची थी। मृतक पक्ष का आरोप है कि पैमाइश पूरी होने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और राजेंद्र पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गुड्डू यादव, धीरेंद्र, पप्पू यादव, शैलेंद्र, आकाश यादव, अनुपम यादव और अमिताभ यादव समेत कई लोगों पर हमले का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर हरदोई पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्व टीम शिकायत की जांच और पैमाइश कर रही थी। निरीक्षण के बाद राजेंद्र पुत्र नेकराम अचानक अज्ञात कारणों से अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी हरपालपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा राजस्व टीम से पूछताछ में अब तक किसी भी प्रकार के झगड़े या मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस मामले में परिजनों के हत्या के आरोप और पुलिस की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष आमने-सामने हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के निष्कर्ष ही यह तय करेंगे कि बुजुर्ग की मौत हमले के कारण हुई या किसी अन्य वजह से।

मानसिक रोगियों के अधिकार और नशामुक्ति पर शाहाबाद में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

वेब वार्ता/हरदोई

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेर्शों के क्रम में सोमवार को तहसील शाहाबाद के उधरनपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर में मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उससे बचाव विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश माननीय रीता कौशिक एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/प्रभारी श्रीमती स्मिता गोस्वामी के निर्देशन तथा तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद की सचिव/तहसीलदार श्रीमती संध्या यादव के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

शिविर की अध्यक्षता काउंसिलर शिवानी तिवारी ने की। उन्होंने उपस्थित बच्चों एवं ग्रामीणों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया तथा शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी।

वहीं लीगल एड क्लीनिक के राघवेंद्र विक्रम सिंह ने मानसिक एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और उन्हें उपलब्ध स्वास्थ्य एवं कानूनी सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में गरिमा और समानता के साथ जीवन जीने, बिना भेदभाव के अवसर प्राप्त करने, उचित स्वास्थ्य सेवाएं लेने तथा नि:शुल्क विधिक सहायता पाने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने बताया कि ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39A तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में सुरक्षित हैं।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि मानसिक या बौद्धिक अक्षमता किसी व्यक्ति को समाज से अलग नहीं करती, बल्कि वह समाज का समान अधिकारों वाला सदस्य है। साथ ही नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी, ग्रामीण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

एक पेड़ मां के नाम' वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत तुलसी पार्क में लगाए गए पौधे

भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने किया नेतृत्व

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। एक पेड़ मां के नाम' वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुलसी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित वातावरण के निर्माण तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का संदेश देते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह अपनी मां के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और

पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायी जनआंदोलन है। उन्होंने सभी कार्यकताओं एवं नागरिकों से अपील की कि वे अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लें। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण समय की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे,तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री बिंदु विश्वकर्मा,जिला मीडिया प्रभारी डी.पी.सिंह 'बैस',राजाराम गौतम,संदीप उपाध्याय,अंशुमाली भारतवंशी,आलोक पांडेय,सौरभ तुलस्यान,हिमांशु शुक्ला सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी कार्यकताओं ने लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में हरदोई ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि

लक्ष्मीकान्त पाठक। वेबवार्ता

हरदोई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में हरदोई ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 की प्रगति के आधार पर विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जनपद ने प्रदेश के शीर्ष-10 जिलों में स्थान बनाया है। यह जानकारी सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में दी गई। अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय सभी विभागों के बेहतर समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न विभागों की प्रगति, जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति, विकास कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा जनशिकायतों की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिन विभागों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई, उन्हें तत्काल सुधार करते हुए जुलाई माह के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि किसी भी योजना में लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक विभाग को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना होगा।

प्रदेश के टॉप-10 जिलों में बनाया स्थान

ताजा खबर

संक्षिप्त

विधानसभा अध्यक्ष की पहल से आत्मसमर्पित 10 नक्सलियों को सरकारी नौकरी

राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ शासन की नक्सली पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके 17 नक्सलियों में से 10 को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके साथ ही, 15 नक्सलियों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की गई। इन नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया गया है। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान से पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के राजनांदगांव स्थित निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान 24 नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को भी चेक वितरित किए गए। इन परिवारों की मांगों को पूरा करते हुए शासन की ओर से सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाना है। यह नीति उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से उन्हें सुरक्षित और स्थायी निवास भी प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के तहत 24 नक्सल पीड़ित परिवारों को भी सहायता प्रदान की गई। इन परिवारों ने नक्सली हिंसा के कारण काफी कठिनाइयों का सामना किया था। सरकार उनकी मांगों को पूरा कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह पहल राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

सिद्धखोल जलप्रपात में ईको-टूरिज्म प्रबंधन से संवर रही स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका

रायपुर। बलौदाबाजार जिले का प्रसिद्ध सिद्धखोल जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। वन विभाग के मार्गदर्शन में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समिति कुकरीकोना द्वारा यहां संचालित किए जा रहे ईको-टूरिज्म प्रबंधन ने न केवल वनों और पर्यावरण के संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है, बल्कि स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक सशक्त माध्यम भी बनकर उभरा है। कुकरीकोना समिति द्वारा स्थानीय ग्रामीण युवाओं को जोड़कर एक %पर्यटन समूह% का गठन किया गया है। ये प्रशिक्षित युवा जलप्रपात क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हैं तथा मानसून के दौरान जलप्रपात के समीप चिन्हित संवेदनशील एवं खतरनाक स्थलों पर मुस्तैद रहकर सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए समिति के काउंटर पर प्राथमिक चिकित्सा किट की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सिद्धखोल के संवेदनशील वनक्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ और प्लास्टिक-मुक्त बनाए रखने के लिए कुकरीकोना समिति द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर पानी की प्लास्टिक बोतलों के लिए ?50 का रिफंडेबल चार्ज लिया जाएगा, जिसे पर्यटकों द्वारा बोतल सुरक्षित वापस लाने पर तुरंत लौटा दिया जाएगा। पूरे परिसर में स्थानीय बांस से बने कूड़ेदान स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैं। साथ ही, समिति की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा पर्यटकों को रियायती दरों पर जूट,कपड़े के थैले और दोना-पत्तल उपलब्ध कराए जाएँगे ।प्रत्येक सोमवार को वन अमले और समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पूरे पर्यटन मार्ग में स्वच्छता श्रमदान चलाकर संपूर्ण कचरे का सुरक्षित निपटान किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा हेतु शुल्क प्रणाली का सरलीकरण*- समिति द्वारा पर्यटकों को सुगम और किफायती अनुभव देने के लिए प्रवेश शुल्क प्रणाली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का न्योता

तुपकी भेंट कर किया सम्मानित

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित उनके निवास पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव तथा वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 600 वर्षों से अधिक समय से निरंतर आयोजित हो रहा गोंचा महापर्व बस्तर की सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और लोक आस्था का प्रतीक है। बस्तर दशहरा के बाद यह क्षेत्र का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है।

समिति ने जानकारी दी कि महापर्व की शुरुआत 29 जून को देव स्नान पूर्णिमा (चंदन यात्रा) के साथ हो चुकी है। इसके अंतर्गत 15 जुलाई को नेत्रोत्सव पूजा, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य गोंचा रथयात्रा तथा 24 जुलाई को बाहुड़ा रथयात्रा के साथ महापर्व का समापन होगा। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बस्तर की पारंपरिक %तुपकी % भेंट कर सम्मानित किया गया। गोंचा महापर्व में तुपकी चलाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। पर्व के दौरान तुपकियों की गूंज से पूरा जगदलपुर उत्सवमय वातावरण में सराबोर हो उठता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निमंत्रण के लिए आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए गोंचा महापर्व की सफल एवं भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी भी उपस्थित रहे।तिनिधिमंडल में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डे, गोंचा समिति के अध्यक्ष मुक्तेश्वर पाण्डे, रजनीश पाणिग्राही, नरेंद्र पाणिग्राही, देवशंकर पंडा, दिलीप पाणिग्राही, विजय पाण्डे, बिभाधार पाण्डे, दिनेश पाणिग्राही, आत्माराम जोशी, विवेक पाण्डे, अर्जुन पाण्डे, भास्कर जोशी, दिलेश्वर पाण्डे, तरुण पाण्डे, जयप्रकाश पाढ़ी, मिनेश पाणिग्राही, सोमप्रकाश जोशी, वेणुधर पाणिग्राही, सुरेंद्र पाणिग्राही, त्रिनाथ आचार्य, गुरुनारायण पाणिग्राही, खिरेंद्र पाण्डे सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

स्वच्छ ईंधन, बेहतर पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार

छत्तीसगढ़ में नई सीबीजी-2026 नीति लागू

रायपुर. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 लागू कर दी है। पिछली कैबिनेट ने सीबीजी नीति को हरी झंडी दी थी। इसके बाद इस नीति को लागू किया गया है। इस नीति में नगरीय निकायों की अहम भूमिका होगी।

नई नीति के तहत गोबर, कृषि अवशेष, पराली और अन्य जैविक कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं निवेशकों को नई औद्योगिक नीति के तहत छूट जारी की जाएगी।

जानें इस नीति के फायदें

आम लोगों को पराली जलाने और जैविक कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी मिलेगी स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे। स्थानीय स्तर पर उद्योग लगने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हरित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।वोफीडस्टॉक पर मंडी शुल्क से राहत मिलेगी। सिंगल विंडो क्लीयरेंस से अनुमतियों की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि और आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग मिलेगा। किसानों को बिजली शुल्क एवं अन्य प्रोत्साहन मिलेंगे। फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सरकारी सहयोग मिलेगा। किसानों को गोबर, पराली और कृषि अवशेष बेचकर अतिरिक्त आय मिलेगी।कृषि कचरे का आर्थिक उपयोग बढ़ेगा। बायो-उर्वरक की उपलब्धता से खेती की लागत में कमी आएगी।

मिलेगा बेहतर माहौल

राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य में बायोगैस आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना है। नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके लिए सिंगल विंडो व्यवस्था और आवश्यक नियमों में सुधार किया गया है।

बाजार पर फोकस

इस नीति में केवल गैस उत्पादन ही नहीं बल्कि उसके लिए बाजार तैयार करने पर भी फोकस किया गया है। परिवहन क्षेत्र को सीबीजी की खपत का प्रमुख माध्यम बनाने की रणनीति बनाई गई है। घरेलू स्तर पर उत्पादित सीबीजी के लिए मांग पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन बसों, निजी वाहनों और नगरीय निकायों के वाहनों को जीएनजी में बदलने के लिए आवश्यक सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नीति की वैधता अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थानों तथा शहरों में संचालित निजी परिवहन ऑपरेटरों को सीएनजी आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंडी शुल्क से राहत का प्रावधान

इस नीति की खास बात यह है कि फीडस्टॉक (कृषि अवशेष एवं जैविक सामग्री) पर मंडी शुल्क से राहत का प्रावधान बनाया गया है। इससे बायोगैस संयंत्रों की लागत कम होगी और किसानों से सीधे सामग्री खरीदने की प्रक्रिया आसान बनेगी। इसका लाभ किसानों को बेहतर मूल्य और निवेशकों को कम परिचालन लागत के रूप में मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

75 हजार खाली पदों पर भर्ती की मांग

अभ्यर्थियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में लंबित सरकारी भर्तियां जल्द शुरू कराने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर युवाओं ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है और उनकी आयु सीमा भी प्रभावित हो रही है।

स्वीकृत पदों पर विज्ञापन जारी न होने से युवा परेशान

अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 700 पदों पर भर्ती के लिए एक वर्ष पहले ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में तीन हजार से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग में पांच हजार शिक्षक पदों के लिए भी स्वीकृति जारी होने के बावजूद अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उनका दावा है कि विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार पद खाली हैं।

बार-बार गुहार के बाद भी अभ्यर्थियों में बढ़ी निराशा

युवाओं ने बताया कि वे लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही देरी से उनमें निराशा बढ़ रही है। उनका कहना है कि वे अब तक छह बार विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा संबंधित मंत्रियों को आवेदन देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर चुके हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की, ताकि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल व कृषि मंत्री नेताम ने पद्म विभूषण तीजन बाई को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रविवार को भिलाई के ग्राम गनियारी स्थित पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई के निवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत लोककला साधिका को नमन किया तथा शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और पंडवानी कला को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी दिवंगत तीजन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा, संघर्ष और समर्पण से छत्तीसगढ़ का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। उनकी कला ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनका निधन कला जगत और पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने तीजन बाई के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मिस्त्री के हाथों ने जब बनाया अपने सपनों का आशियाना

रायपुर। बरसों तक दूसरों के लिए ईंट-पत्थरों से सपनों का घर खड़ा करने वाले श्यामसिंह चंद्रवंशी के मन में भी एक छोटा-सा सपना पलता था। एक ऐसा पक्का घर, जिसमें उनका परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मोहला के ग्राम गुहाटोला निवासी श्यामसिंह खेती के साथ राजमिस्त्री का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण उनका परिवार वर्षों तक कच्चे मकान में रहने को विवश था। बरसात के दिनों में टपकती छत, तेज हवाओं का डर और हर मौसम में परिवार की सुरक्षा की चिंता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आई। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता ने उस सपने को आकार देना शुरू किया, जिसे वे वर्षों से अपने मन में संजोए हुए थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि एक मिस्त्री होने के नाते उन्होंने अपना घर किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से तैयार किया।

रायपुर में डीईओ ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण

स्कूलों में साफ-सफाई जैसी खामियां मिलीं, समय पर सिलेबस पूरा करने के दिए निर्देश

रायपुर. रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शनिवार को धरसींवा विकासखंड के शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों की साफ-सफाई, शिक्षकों की उपस्थिति, वीएसके ऐप में दर्ज जानकारी और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित अधिकारियों और प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

डीईओ ने सबसे पहले भनपुरी स्थित काशीराम शर्मा शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय (सेजेस) का निरीक्षण किया। यहां तीन शिक्षकों के मैनुअल अवकाश आवेदन मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और ऑनलाइन आवेदन नहीं करने का कारण पूछा। साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक व्याख्याता के लंबे समय से अनुपस्थित रहने का मामला भी सामने आया, जिस पर जांच रिपोर्ट भेजने को कहा गया।

छात्राओं को साइकिल वितरित की

निरीक्षण के दौरान डीईओ ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से बातचीत कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए नियमित अध्ययन करने की सलाह दी और विशेष रूप से गणित और बायोलॉजी जैसे विषयों की तैयारी पर ध्यान देने को कहा।

तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 29 जवानों को दी श्रद्धांजलि

राजनांदगाँव। 12 जुलाई वर्ष 2009 को अविभाजित राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों की शहादत हो गई थी। उनकी शहादत की बरसी पर वीर शहीदों को नमन करने प्रतिवर्ष की भांति आज भी पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के कोरकोट्टी, सीता गांव और मदनवाड़ा में नक्सलियों के हमले में अपनी जान गंवाने वाले तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 अन्य पुलिस जवानों के तैल चित्र पर कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहादत को नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद स्वर्गीय एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि यह दिन काफी भावुक और गर्व करने वाला दिन है, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी शहीदों की कुर्बानी याद रखें और अमन-शांति कायम रहे। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब भय और हिंसा मुक्त राज्य होने से और ज्यादा प्रगति होगी। इस दौरान मौजूद सांसद संतोष पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से अब काफी परिवर्तन आया है, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संकल्प से प्रदेश नक्सलमुक्त हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में भूतपूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव,पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम, सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शहीद परिवार और पुलिस परिवार के लोग सहित स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

देवकीनंदन ठाकुर बोले : मंदिरों के फंड का हुआ गलत इस्तेमाल, अमरनाथ यात्रा की पवित्रता पर दिया जोर

देवकीनंदन ठाकुर ने मंदिर फंड, शिक्षा और अमरनाथ यात्रा पर रखे विचार

रायपुर। मुसलमान के बच्चे ईमानदार हैं, ईसाई के बच्चे ईमानदार हैं, क्योंकि वो कुरान और बाइबिल पढ़ते हैं. लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि वो गीता नहीं पढ़ते हैं. हमने बच्चे को हाऊ टू अर्न मनी सिखाया है. गीता-महाभारत का ज्ञान नहीं दिया. यह बात प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सनातनी के तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कही.

कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर रायपुर के बुढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 8 से 14 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे. आयोजन के पहले रविवार को कथा वाचक कथा आयोजक योगेश अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ चर्चा में तत्कालीन विषयों पर, खासतौर से धर्म से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए. देवकीनंदन ठाकुर ने मंदिरों में कथित गबन और अमरनाथ यात्रा को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चोरी पर अधिक ध्यान देने से सनातन धर्म की बदनामी हो सकती है। चोरी अन्य स्थानों पर भी होती है। उन्होंने आजादी के बाद से सरकारों पर मंदिर के फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।

कुछ बड़ा करने वाले हैं मोदी

राम मंदिर में चोरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन रहने पर कथा वाचक ने कहा कि अगर मोदी जी मौन हैं, तो कुछ बड़ा करने वाले है. कुछ बड़ा होने वाला है. ऐसा मेरा मानना है.

स्कूल में पढ़ाएं चरित्र वाला सब्जेक्ट

स्कूलों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर तंज कसते हुए कथा वाचक ने कहा कि आज छोटे-छोटे बच्चों को बॉलीवुड गाना पर नचाया जा रहा है. छोटे-छोटे बच्चों को छैया-छैया गाने में नचाया जा रहा है. गुरु को चरित्रवान बनाया जाना चाहिए. टीचर क्या सिखा रहा है? इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे बॉलीवुड गाने पर डांस न करें. सावित्री, लक्ष्मी बाई, सीता की अभिव्यक्ति करे. चलाना है तो स्कूल चलाएं, लेकिन चरित्र वाली सब्जेक्ट सिखाएं.

ठाकुर ने %सनातन बोर्ड% बनाने का सुझाव दिया। यह बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह काम करेगा। इसमें चार शंकराचार्य, पांच वैष्णवाचार्य और अन्य धार्मिक नेता शामिल होंगे। इस फंड का उपयोग गरीब लोगों की मदद, आधुनिक गुरुकुलों को सहारा देने और गौ-सेवा के लिए किया जा सकता है। इससे भारत विश्व-गुरु बन सकता है। उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे भागने वाले ही चोरी या गबन करते हैं। रायपुर में कई आदिवासी पैसे की कमी से दूसरे धर्म अपना लेते हैं। मंदिर के फंड का उपयोग उनकी सेवा के लिए होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड ही सही समाधान है। धर्म से जुड़े मामले संतों और धार्मिक नेताओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी चाहिए। जब धार्मिक नेता समाज की सेवा में खुद को समर्पित करेंगे, तो चोरियां बंद हो जाएंगी। सनातन बोर्ड के जरिये सनातन परंपरा और भी फलेगी-फूलेगी।अमरनाथ यात्रा को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाबा अमरनाथ का शिवलिंग जल्दी ओझल हो गया। इसका मतलब है कि यात्रा की पवित्रता और मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सनातनियों से तीर्थ स्थल को पवित्र तीर्थ मानने की अपील की। इसे सिर्फ घूमने-फिरने की जगह न समझें। पिकनिक मनाने या गर्मी से बचने के लिए वहां न जाएं। वहां तभी जाएं जब मन पवित्र हो और महादेव के धाम जाने की सच्ची पुकार हो। उन्होंने भीड़ को लेकर संयम बरतने को कहा। हो सके तो पूरे परिवार के बजाय घर से सिर्फ एक व्यक्ति ही यात्रा पर जाए। देवकी नंदन ठाकुर ने संसद में धर्मांचरित लोगों के जाने की बात कहते हुए कहा कि 50 सीट आरक्षित कर देना चाहिए. लिविंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. वेश्यावृती को लीगल कर दिया है. समलैंगिग का कानून बन गया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

साल के अंत में नेपाल दौरे पर जाएगी भारत ए टीम

- मुम्बई। भारत ए क्रिकेट टीम इस साल के अंत में नेपाल का दौरा करेगी। इस दौरे में भारत एक नेपाल टीम से तीन मैचों की सीरीज खेलेगी इससे नेपाल टीम को काफी लाभ होगा। दोनो ही देशों के क्रिकेट बोर्ड इस दौर को लेकर सहमत हैं।इस दौरे में सभी मुकाबले नेपाल के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेले जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण दौरे को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग हुए आईसीसी के सालान सम्मेलन के दौरान तय किया गया था।। इस अवसर पर नेपाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद और सचिव पारस खड़का ने भारतीय बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया के साथ मुलाकात की थी, जिसमें दोनों बोर्डों ने सर्वसम्मति से इस सीरीज पर अपनी मुहर लगाई। इससे दोनो देशों के बीच खेल संबंध बेहतर होंगे।

सीरीज का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पहला टी20 मुकाबला 9 दिसंबर 2026 को होगा, जिसके बाद दूसरा मैच 11 दिसंबर 2026 को और तीसरा व अंतिम मैच 13 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। तीनों ही मैच त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में ही खेले जाएंगे, जिससे प्रशंसकों को लगातार तीन दिनों तक रोमांचक क्रिकेट देखने का अवसर मिलेगा।

रमीज ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे से पहले कप्तान बदलने पर उठाये सवाल

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट में विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौर से पहले एक बार फिर कप्तान बदलने पर पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने सवाल उठाये हैं।

राजा ने कहा कि ये गलत कदम है, जिस प्रकार से शान मसूद को हटाकर बाबर आजम को कप्तानी सौंपी गयी है उससे कोई लाभ नहीं होगा। पूर्व में पीसीबी प्रमुख रहे रमीज के अनुसार खराब प्रदर्शन पर केवल कप्तान को बदलने से कुछ नहीं होने वाला।

रमीज कहा कि जब किसी कप्तान को लगातार साधारण खिलाड़ियों का समूह दिया जाता है, तो आप बेहतर परिणाम किया प्रकार से मिल सकते हैं। साथ ही पूछा है

कि अगर टेस्ट टीम का स्तर अच्छा नहीं है, तो केवल कप्तान क्या कर सकता है? रमीज के अनुसार क कप्तान की सफलता पूरी तरह से उसे मिली टीम पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे खिलाड़ी उसे दिए जाते हैं। अपने इस बयान से रमीज ने पीपीसी पर करारा तंज किया है।

गौरतलब है कि शान ने दिसंबर 2023 से 16 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। इसमें टीम को 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों के लिहाज से यह प्रदर्शन अच्छा नहीं है पर रमीज का कहना है कि इस प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से मसूद को दोषी बताना सही नहीं है क्योंकि उन्हें एक कमजोर टीम दी गयी थी। रमीज ने कहा कि बाबर भी इस टीम के साथ बेहतर परिणाम नहीं दे पायेंगे क्योंकि शान जैसी चुनौतियों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। केवल कप्तान बदलने से टीम की मूल संरचना और खिलाड़ियों की गुणवत्ता नहीं बदलती। पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खेलाफ इसी माह दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके बाद अगस्त और सितंबर में पाक टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां उसे तीन टेस्ट खेलने हैं। इन दौरों पर बाबर की कप्तानी की कड़ी परीक्षा होगी, और रमीज की टिप्पणियां निश्चित रूप से उन पर और पीसीबी पर दबाव बढ़ाएंगी।

गांगुली और द्रविड़ के कारण संन्यास पर मजबूर हुए थे मांजरेकर

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर अपने समय के एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं पर इसके बाद भी उनका करियर उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। मांजरेकर ने इसके पीछे सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के छा जाने को बताया है जिसके कारण उन्हें असमय ही संन्यास के लिए मजबूर होना पड़ा है। मांजरेकर जब भारतीय क्रिकेट में आये थे तब उनकी बल्लेबाजी तकनीक देखकर लोगों को उनमें सुनील गावस्कर की छवि नजर आयी। इस क्रिकेटर को क्रिकेट विरासत में मिला था। उनके पिता विजय मांजरेकर जिन्होंने टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन न सिर्फ खेलेगा, बल्कि टीम इंडिया की जर्सी भी पहनेगा जो आखिरकार सच भी हुआ।

मांजरेकर जब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले, उनकी पहचान एक तकनीकी रूप से बेहद सक्षम और ठोस बल्लेबाज के तौर पर रही। विशेष रूप से विदेशी पिचों पर उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार और अनुकरणीय था। उनकी इसी लाजवाब बल्लेबाजी तकनीक के कारण साथी खिलाड़ी उन्हें कई बार मिस्टर परफेक्ट कहकर

पुकारते थे। हालांकि तब सचिन तेंदुलकर उन्हें अनूठे व्यक्तित्व के कारया मिस्टार डिफरेंट नाम से बुलाते थे।

इतनी क्षमताओं के बाद भी मांजरेकर अपने करियर में वह ऐतिहासिक बुलंदी हासिल नहीं कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। इसकी वहज उन्हें साल 2018 में लॉन्च हुई अपनी आत्मकथा इंपर्फेक्ट में बतायी है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ और गांगुली के उभरने से उनका अंतरराष्ट्रीय करियर समय से पहले ही समाप्त हो गया।

मांजरेकर ने अपनी किताब में लिखा कि जब उन्होंने खेल को अलविदा कहने का मन बनाया, तब वे टीम के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे और आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं थे। लेकिन 1996 के ऐतिहासिक इंग्लैंड दौरे ने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उस दौरे पर द्रविड़ और गांगुली का प्रदर्शन देखकर उन्हें लगा कि अब संन्यास लेन ही सही है। तब वे वे समझ चुके थे कि अब उनका समय पूरा हो गया है और युवाओं के लिए रास्ता छोड़ना ही बेहतर होगा। संन्यास लेने के बाद मांजरेकर ने एक कमेंटेटर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनायी। अपनी बेबाक राय के चलते वह कई बार विवादों में भी घिरे। मांजरेकर अपनी किताब में सचिन की आलोचना करने में भी पीछे नहीं रहे। मांजरेकर ने लिखा कि जब सचिन अपने करियर के अंतिम पड़ाव से गुजर रहे थे, तब कई बार उनकी खराब फॉर्म के बाद भी वह टीम में जमे रहे जिससे उभरत हुए खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ।

भारतीय टीम को विदेशी पिचों के अनुसार भी खेलना सीखना होगा : डोइशे

लंदन। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने कहा है कि उसे विदेशी हालातों के अनुसार ढ़लना सीखना होगा। डोइशे के अनुसार भारतीय टीम अभी विदेशी पिचों के अनुरुप ढ़ल नहीं पा रही है। इसी कारण उसके बल्लेबाज असफल हो रहे हैं। कोच के अनुसार टीम को अलग-अलग माहौल के अनुकूल अपने को जल्दी ढालने की प्रक्रिया को समझना होगा और उसी को देखते हुए खेलना होगा।

डोइशे ने कहा, हमने इस दौरे में अपने को ढालने के बारे में काफी चर्चा की है। यह कहना आसान है कि हमें अनुकूलन करना चाहिए, लेकिन हमें उस प्रक्रिया को समझना

होगा कि इसके लिए वास्तव में क्या करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक तौर पर, भारतीय टीम के लिए यह समझना सबसे बड़ी चुनौती है कि हम विदेशी हालात में क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की ओर देखने और दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तैयारियों की सलाह दी है क्योंकि वहां उन्हें एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना होगा।

सहायक कोच ने कहा हमें ऐसी टीम चाहिये जो भारतीय मैदानों के आलावा विदेशी धरती पर भी उसी प्रकार से खेल सके। उन्होंने कहा कि टीम को विदेशी स्थानों पर भी अच्छा खेलना सीखना होगा। इसके लिए केवल टीम को अपनी मानिकता में बदलाव लाना है क्योंकि भारत में जहां सपाट पिच हैं वहीं विदेशों में तेज और उछला भरी पिचें हैं।

इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर भारतीय टीम को तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिचों पर खासी परेशानी हुई। भारत की सपाट पिचों पर बेजोड़ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वहां अपनी लय नहीं पकड़ पाए। टेन डोइशे ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के बेहतरीन प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि हम उस तरह से खुद को ढाल नहीं सके जिसकी बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह समझना आवश्यक है कि जो रणनीति और तकनीक भारत में सफल होती है, वह जरूरी नहीं कि विदेशी धरती पर भी उतनी ही कारगर साबित हो।

मैक्सवेल सहित इन बल्लेबाजों के नाम है टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक शतक

मुम्बई। टी20 अंतरराष्ट्रीय, क्रिकेट में अब तक सबसे अधिक शतक लगाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाजों में दो भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं। इस प्रारुप में सबसे अधिक पांच-पांच शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के रोहित शर्मा के नाम हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह और इंग्लैड के फिल साल्ट हैं भी इस सूची में शामिल हैं।

ग्लेन मैक्सवेल : ऑस्ट्रेलियई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने अब तक 5 बेमिसाल टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाये हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। 130 मैचों की 118 पारियों में उन्होंने 154.42 के शानदार स्ट्राइक रेट से 2897 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 145 रन रहा है, और उन्होंने अपने करियर में 243 चौके और 150 छक्के जड़े हैं, जो उनकी मारक क्षमता को दर्शाता है।

रोहित शर्मा : रोहित ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में 5 शानदार शतक लगाए हैं और इस प्रारूप में सर्वाधिक रन (4231) बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। साल 2007 के पहले टी20 विश्व कप से अपने सफर की शुरूआत करने वाले रोहित ने 159 मैचों की 151 पारियों में 140.89 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाये हैं। उनके नाम 32 अर्धशतक और नाबाद 121 रन का उच्चतम स्कोर भी है। अपनी बेजोड़ टाइमिंग और ताकत से उन्होंने रिकॉर्ड 383 चौके और 205 छक्के जड़े हैं, जो उन्हें टी20ई का सबसे सफल बल्लेबाज बनाता हैं हालांकि अब उन्होंने इस प्रारुप से संन्यास ले लिय है।

करनबीर सिंह : इस विशिष्ट सूची में तीसरा नाम ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह का है। एसोसिएट नेशन की ओर से खेलने वाले करबीर ने सिर्फ 60 मैचों की 59 पारियों में 4 शतक लगाकर सबको हैरान किया है। 48.71 की हैरतअंगेज औसत और 175.41 के तूफानी स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2533 रन बनाए हैं। करनबीर का सर्वोच्च स्कोर 164 रन है, जो इस सूची में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। फिल साल्ट : चौथे स्थान पर इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट हैं। साल 2022 में डेब्यू करने के बाद से साल्ट ने है। 64 मैचों की 59 पारियों में उन्होंने 4 शतक और 10 अर्धशतकों के साथ 164.52 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 1846 रन बनाए हैं। साल्ट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 141 रन रहा है, और उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से 186 चौके और 87 छक्के लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव : इस इसी में भारत के सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं। साल 2021 में पदार्पण करने के बाद से ही सूर्या ने टी20 क्रिकेट खेलने में अपनी क्षमता दिखायी है। उन्होंने 113 मैचों की 107 पारियों में 4 शतक और 25 अर्धशतकों की मदद से 3272 रन बनाए हैं।

कारोबार

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सोना-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान तनाव और फेड के सख्त रुख की वजहों से सोने-चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। सोने-चांदी के कारोबार की सोमवार को सुस्त शुरूआत हुई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 845 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,633 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 1,43,478 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 1,658 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,820 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 1,43,633 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 1,41,557 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव की शुरूआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 4,016 रुपये की गिरावट के साथ 2,18,648 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 2,22,664 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 4,889 रुपये की गिरावट के साथ 2,17,775 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 2,18,667 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 2,17,277 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 4,106.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 4,113.70 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 38.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,075.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 59.71 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला बंद भाव 60.16 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 1.40 डॉलर की गिरावट साथ 58.76 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरूआत

सेंसेक्स 600 अंक टूटकर 76,900, निफ्टी 24,000 के स्तर पर

मुंबई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कमजोरी के साथ शुरूआत की।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई। सुबह शुरूआत के बाद निफ्टी 50 178 अंक की गिरावट के साथ 24,029.75 पर कारोबार कर रहा था। वहीं बीएसई सेंसेक्स 637 अंक टूटकर 76,931.95 के स्तर पर आ गया। यह गिरावट केवल प्रमुख सूचकांकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी क्रमशः करीब 0.58 प्रतिशत और 0.56

प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो व्यापक बिकवाली का संकेत है। सेक्टरवार देखें तो बैंकिंग, ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल शेयरों पर भारी दबाव रहा। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस शामिल रहे। हालांकि, इस बिकवाली के माहौल में भी कुछ चुनिंदा आईटी और पावर सेक्टर के शेयरों ने मजबूती दिखाई। टीसीएस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक और पावर ग्रिड के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा मिला। बाजार के जानकारों ने मौजूदा गिरावट को शुक्रवार की तेजी के विपरीत बताया। उन्होंने याद दिलाया कि शुक्रवार को निफ्टी 50 244 अंक की बढ़त के साथ 24,206.90 पर बंद हुआ था, जिसमें वित्तीय और आईटी शेयरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,604 करोड़ रुपये और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,020 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की थी, जबकि इंडिया वीआईएक्स में कमी बाजार में अस्थिरता घटने का संकेत दे रही थी। आज का कमजोर प्रदर्शन वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों के दबाव को दशार्ता है। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए, जहां एनवीडिया और मेटा जैसी टेक कंपनियों में खरीदारी देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर निवेशकों का उत्साह अभी भी बना हुआ है। हालांकि, एशियाई बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख है।

एप्पल ने दायर कराया ओपनएआई पर मुकदमा, तकनीकी चुराने का है आरोप

नई दिल्ली। एआई फर्म ओपनएआई और उसके मुख्य हार्डवेयर अधिकारी, टैंग टैन के खिलाफ एप्पल कंपनी ने कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का आरोप है कि ओपनएआई ने सुनियोजित तरीके से उसके आगामी उत्पादों से जुड़ी गोपनीय जानकारी, डिजाइन और तकनीकी दस्तावेजों को हासिल करने का प्रयास किया।

मुकदमे में यह दावा किया गया है कि टैंग टैन, जो पहले एप्पल में प्रोडक्ट डिजाइन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स सहित कई प्रमुख हार्डवेयर उत्पादों का नेतृत्व किया था, उन्होंने नौकरी के इंटरव्यू के दौरान एप्पल के कर्मचारियों को कंपनी के आने वाले उत्पादों से संबंधित जानकारी, कंपोनेंट्स, ड्रॉइंग और अन्य गोपनीय सामग्री साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। एप्पल ने अपनी शिकायत में पूर्व आईफोन हार्डवेयर इंजीनियर चांग लियू का भी नाम लिया है।

कंपनी का आरोप है कि चांग लियू ने ओपनएआई के लिए हार्डवेयर विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान गैरकानूनी रूप से एप्पल की दर्जनों गोपनीय हार्डवेयर फाइलों तक पहुँच बनाई। इन फाइलों में ऐसे उत्पादों से जुड़ी विस्तृत तकनीकी जानकारी और इंजीनियरिंग प्रेजेंटेशन शामिल थे, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, एप्पल ने यह भी आरोप लगाया कि ओपनएआई ने अपने कई कर्मचारियों को यह सलाह दी कि वे कंपनी छोड़ते समय इस प्रकार से कदम उठाएं, जिससे गोपनीय फाइलों तक उनकी पहुँच बनी रहे, जो कॉर्पोरेट गोपनीयता समझौतों का उल्लंघन है। हालांकि, ओपनएआई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसे किसी अन्य कंपनी के व्यापारिक रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह ऐसी नई तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो दुनिया भर के लोगों को सशक्त बना सके।

यह ध्यान देने योग्य है कि हाल के वर्षों में एप्पल और ओपनएआई के बीच एक करीबी साझेदारी रही है, जिसमें ओपनएआई ने एप्पल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और सिरी डिजिटल असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान की थी। फिर भी, पिछले एक साल में दोनों कंपनियों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है, जिसकी एक वजह ओपनएआई द्वारा एप्पल के पूर्व चर्चित डिजाइन प्रमुख जॉनी इवे को नए डिवाइस विकसित करने के लिए अपने साथ जोड़ना भी बताया गया है। मुकदमे में एप्पल ने यह भी दावा किया है कि ओपनएआई ने अपने प्रस्तावित आईपीओ से कुछ महीने पहले एप्पल के लगभग 400 कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ लिया। एप्पल का आरोप है कि तकनीकी स्टाफ से लेकर मुख्य हार्डवेयर अधिकारी तक, हर स्तर पर ओपनएआई ने अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ मिलकर एप्पल के व्यापारिक रहस्य और गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की।

रुपया 39 पैसे टूटकर 95.77 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था

मुंबई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच रुपया सोमवार को शुरूआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 39 पैसे टूटकर 95.77 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 79 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि घरेलू मुद्रा के कमजोर शुरूआत के साथ 95.53 प्रति डॉलर के स्तर पर खुलने की उम्मीद थी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.72 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 95.77 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर

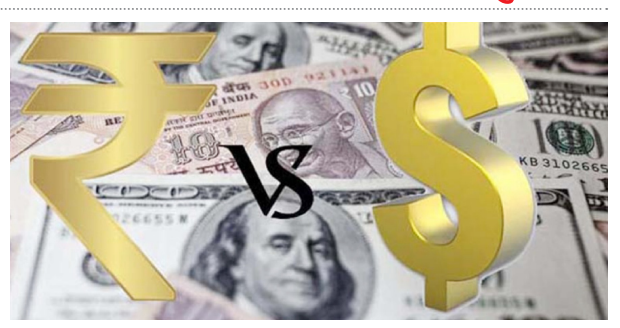

गया। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले नौ पैसे मजबूत होकर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 प्रतिशत बढ़कर 101.12 पर कारोबार कर रहा था।

महत्वपूर्ण ख़बर

हरियाली के रंग सहेलियों के संग थीम पर ग्रीन फिएस्टा आयोजित किया

■ इन्दौर। हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते श्री नागर चित्तौड़ा सखी संगठन द्वारा ग्रीन फिएस्टा- हरियाली के रंग सहेलियों के संग थीम पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया जिसमें ग्रीन ड्रेस अप में शामिल हो सदस्याओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह की शुरूआत समय पर पहुंचने वाली सदस्यों को अर्ली बड्र्स प्राइज देकर की गई। इसके बाद मनोरंजक गेम्स, तंबोला और ग्रीन क्वीन प्रतियोगिता की गई। सभी प्रतिभागियों को तुलसी के पौधे भेंट किए गए और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उनके पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया।

मुख्यमंत्री ने श्रीमती गंगा मकवाणा के निधन पर शोक व्यक्त किया

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा की माताजी श्रीमती गंगा मकवाणा के निधन पर दु:ख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन को यह असहनीय दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

निमार्णाधीन श्री परशुराम धाम का भूमिपूजन सम्पन्न

■ इन्दौर। आचार्यों और विद्वान पंडितों के सान्निध्य में वेद मंत्रों के साथ समीपस्थ ग्राम तिल्लौर खुर्द में बनने वाले श्री परशुराम धाम के भूमिपूजन के साथ ही धाम का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अभिजीत मुहूर्त में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वेद मंत्रों के बीच भगवान परशुराम के जयघोष गूंजते रहे।

महिला सशक्तिकरण में लाड़ली बहना योजना क्रांतिकारी पहल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बहनों को सशक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिलाएं परिवार की रीढ़ और इज्जत होती हैं। सनातन संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिये प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जो निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बहनों को सशक्त बनाना अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। वे चाहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएं प्रमुख भूमिका में रहें। महिला कल्याण और सशक्तिकरण की यही नीति मध्यप्रदेश सरकार की भी है। प्रदेश की लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को भिंड जिले के लहार में लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिंड जिले को 322 करोड़ लागत के 56 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 4 सांदीपनि विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लहार में विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय स्तर पर पीजी कक्षाओं की सुविधा में वृद्धि करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की समृद्धि, सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। बहनों और बेटियों के साथ युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे नौकरी पाने में नहीं, बल्कि नौकरी प्रदान करने में सक्षम बनें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कतिपय लोग महिला कल्याण कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों ने स्वयं तो कभी भी

लाड़ली बहना जैसी कारगर योजना प्रारंभ नहीं की, अब वे निंदा के अलावा कुछ नहीं करते। यह सर्वविदित है कि लाड़ली बहना योजना में बहनों को दी जा रही राशि परिवार में खुशियां लाने का माध्यम बनी हैं। हमारी बहनें लक्ष्मी, सरस्वती और जगदम्बा का स्वरूप हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ रहा है। देश का इतिहास बदल रहा है। अब महिला आरक्षण की पहल से इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ होगा। कतिपय लोगों ने महिला आरक्षण के प्रावधान में बाधा बनने का कार्य किया है, लेकिन अंततः बहनों को सशक्त बनाने के प्रयास सफलता प्राप्त करेंगे।

राज्य में सुगम परिवहन सेवा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा भी प्रारंभ की जा रही है। कई वर्ष से हमारी बहनों और बेटियों के साथ सभी

भिंड जिले में लिखा जा रहा है विकास का नया अध्याय

नागरिकों को ऐसी सेवा की आवश्यकता थी। राज्य शासन द्वारा इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भिंड जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भिण्ड का जवान सीमा की रक्षा करता है और किसान खेती से अपनी पहचान बनाता है। इस अंचल का संबंध महाभारत से जोड़ा जाता है। लहार नामकरण यहां लाक्षागृह के होने से हुआ, ऐसी मान्यता है। इस अंचल पर हनुमान जी की भी विशेष कृपा है। भिंड जिले के साहसी जवान भारतीय सेना में बड़ी संख्या में शामिल हैं। भिंड के बीहड़ कभी दस्यु समस्या के कारण जाने जाते थे, अब यह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। शिवपुरी जिले में हाल ही में सैन्य क्षेत्र में उपयोगी

ग्वालियर-चंबल अंचल की प्रगति को मिल रहे नए आयाम

लंबी दूरी तक तेज मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल की इकाई प्रारंभ करने की पहल हुई है। चंबल, ग्वालियर क्षेत्र में समग्र प्रगति के प्रयास हो रहे हैं। यहां विकास को नए आयाम मिलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भिंड जिले के जिन विकास कार्यों की शुरूआत हो रही है, उनमें 4 सांदीपनि विद्यालों की सौगात भी शामिल है। इतिहास गवाह है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मैत्री का उदाहरण सांदीपनि आश्रम था, अतः राज्य शासन ने सांदीपनि विद्यालय का नाम देकर विद्यार्थियों को समानता के महत्व से भी अवगत करवाया है। सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आराध्य श्यामाप्रसाद

प्रदेश में शीघ्र प्रारंभ होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

मुखर्जी की प्रेरणा से प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसी माह लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ ही नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से बैठकों में चर्चा भी की गई। प्रदेश में इस दिशा में क्रियान्वयन इसी माह प्रारंभ करने की तैयारी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने भी नई व्यवस्था का समर्थन किया है। यूसीसी का उद्देश्य प्रदेश में व्यक्तिगत और पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संबंधित विषयों का संचालन पृथक-पृथक प्रावधानों के स्थान पर समान रूप से किए जाने की व्यवस्था लागू करना है।

शाजापुर पुलिस ने डकैती की तैयारी विफल की

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शाजापुर जिले की मक्सी थाना पुलिस ने डकैती की एक बड़ी वारदात होने से पहले ही विफल करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के कब्जे से पूर्व में हुई लूट का लगभग 4 लाख 50 हजार मूल्य का सोना-चांदी, डकैती की तैयारी में प्रयुक्त कार, गैस कटर सहित लगभग 16 लाख 50 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस अधीक्षक शाजापुर श्रीमती प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में थाना मक्सी पुलिस को सूचना मिली थी कि मक्सी बायपास स्थित एबी रोड ब्रिज के नीचे कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर गठित पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे तथा गिलोल से पत्थर चलाकर पुलिस दल पर हमला किया। आरोपियों को पकड़ने के दौरान एक आरोपी ने स्क्रू-ड्राइवर से आरक्षक श्री चन्द्रशेखर जाट पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बावजूद पुलिस टीम ने साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 20 जून को हुई एक लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा लूटा गया सोना-चांदी सिरोलिया के जंगल में छिपाकर रखने की जानकारी दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 4 लाख 50 हजार रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए। साथ ही डकैती की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले गैस कटर सहित अन्य उपकरण एवं कार भी जब्त की।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आरोपियों से अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रदेशभर में संगठित अपराध, लूट, डकैती एवं अन्य गंभीर अपराधों के विरुद्ध इसी प्रकार सतत एवं सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नेशनल हाईवे-44 पर कुरई थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में रविवार रात इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियों से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई।

जबलपुर, वेब वार्ता

सूचना मिलते ही कुरई पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा समय रहते आग पर काबू पा लिया। इससे पास स्थित पेट्रोल पंप तक आग पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा टल गया।

पुलिस के अनुसार, ट्रक चेन्नई से नोएडा जा रहा था। रात करीब 9 बजे ट्रक चालक राम सिंह यादव (43), निवासी ग्राम औरैया, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), मोहगांव में सड़क किनारे वाहन खड़ा कर भोजन करने गया था। इसी दौरान ट्रक में अचानक आग भड़क उठी।

स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना देने के साथ ही प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सिवनी से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया जिससे दो गाड़ियां तत्काल मौके पर रवाना हुई जो समय पर पहुंच गई। पुलिस और दमकल विभाग की कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

परन्तु आग बुझने के बाद भी ट्रक में रखी इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग होने वाली आठ बैटरियों की प्लेटें लंबे समय तक अत्यधिक गर्म बनी रहीं। इससे बीच-बीच में धुआं और छोटी-छोटी लपटें उठती रहीं। एहतियात के तौर पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम देर रात तक मौके पर तैनात रही और लगातार कूलिंग की प्रक्रिया जारी रखी, ताकि दोबारा आग न भड़क सके।

दोबारा सुलगने की आशंका बनी रहती है

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, लिथियम आधारित बैटरियों में आग लगने की घटनाएं सामान्य आग की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनमें दोबारा सुलगने की आशंका बनी रहती है।

हॉर्न बजाने पर भड़का युवक, कार पर चढ़कर की तोड़फोड़

इंदौर (वेब वार्ता)। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में रविवार रात एक दंपती को बीच सड़क पर खड़े युवक को हॉर्न बजाना भारी पड़ गया। मामूली बात पर गुस्साए युवक ने कार के बोनट पर चढ़कर जमकर उत्पात मचाया और कार के सामने सहित अन्य शीशे तोड़ दिए।

पूरी घटना कार में बैठे दंपती ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सिंधी कॉलोनी निवासी बाबू पंजवानी अपनी पत्नी के साथ कार से गुजर रहे थे। पलासिया चौराहे के पास शराब दुकान के सामने एक युवक बीच सड़क पर खड़ा था। रास्ता खाली कराने के लिए दंपती ने हॉर्न बजाया। इसी बात से युवक आगबबूला हो गया। युवक पहले कार के बोनट पर हाथ मारने लगा और देखते ही देखते बोनट पर चढ़ गया। इसके बाद उसने कार के सामने का शीशा और अन्य कांच तोड़ दिए। घटना के दौरान दंपती कार के अंदर ही मौजूद रहे और उन्होंने पूरी वारदात अपने मोबाइल में कैद कर ली। घटना के बाद दंपती रावजी बाजार थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है। रावजी बाजार थाना पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है।

घर का रास्ता भटकी 03 वर्षीय मासूम बालिका को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

भोपाल। सतना जिले के थाना कोलगवां क्षेत्र में डायल- 112 जवानों की संवेदनशील एवं तत्पर कार्रवाई से घर का रास्ता भटक गई 03 वर्षीय मासूम बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया गया। समय पर की गई इस मानवीय पहल से बालिका को सुरक्षा एवं परिवार का सान्निध्य पुनः प्राप्त हो सका। 10 जुलाई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोलगवां क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड पर एक 03 वर्षीय बालिका अकेली मिली है, जो घर का रास्ता भटक गई है एवं पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही कोलगवां थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टाफ प्रधान आरक्षक श्री नीरज सिंह एवं पायलट श्री पुरुषोत्तम ने मौके पर पहुँचकर बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लिया। स्नेहपूर्वक पूछताछ करने पर बालिका अपनी कम आयु के कारण परिजनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकी।

चेक बाउंस प्रकरण में कोर्ट का नजीर निर्णय

इन्दौर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने चेक बाउंस प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी फकरूद्दीन हुसैन को दोषी करार देते 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुना पीड़ित पक्ष राजेंद्र विजयवर्गीय को 12.67 लाख प्रतिकर राशि अदा करने का भी आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोग पैरवी एडवोकेट रविन्द्र माहेश्वरी ने की। एडवोकेट माहेश्वरी के अनुसार कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि निर्णय की तारीख से भुगतान होने तक प्रतिकर राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। आरोपी निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करता है तो अतिरिक्त 3 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। एडवोकेट रविंद्र माहेश्वरी के अनुसार करीब दस वर्ष पुराने चेक बाउंस प्रकरण में दिए कोर्ट के इस निर्णय को चेक बाउंस मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिकर राशि के साथ ब्याज और भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है।

रवीन्द्र भवन में सम्मानित हुई दक्षिण-पश्चिम भोपाल की 591 प्रतिभाएं

बुद्धिमत्ता के बलबूते विश्व में पहचान बना सकते हैं युवा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे युवा अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बलबूते प्रदेश और देश ही नहीं पूरे विश्व में पहचान बना सकते हैं। जिस तरह एक सामान्य परिवार से आए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सम्पूर्ण संसार में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, यह एक अनोखा उदाहरण है जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में वैक्सीन के माध्यम से भारतवासियों ही नहीं अन्य राष्ट्रों के नागरिकों का जीवन बचाने का कार्य भी किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का लाभ करोड़ों नागरिकों को दिलवाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को रवींद्र भवन, भोपाल के हंसध्वनि सभागार में नवप्रयाग सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति, भोपाल द्वारा दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्देशक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह, डॉ. मिनी मेहरा, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती आरती अनेजा उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सम्मनित हो रहे विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि भिन्न-भिन्न क्षेत्र की प्रतिभाएं परिश्रम की पराकाष्ठा, अपने संस्कार अपनी युक्ति और बुद्धि से, समय का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण के महासंकल्प को पूरा करने का प्रयास करती हैं। ये प्रतिभाएं सम्मानित होकर स्वयं का नया परिचय भी प्राप्त करती हैं। भोपाल की सुश्री चांदनी विश्वकर्मा ने कक्षा 12वीं में प्रावीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा देश को स्वतंत्रता मिलने के पूर्व भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए नौकरी करने के स्थान पर स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणोत्सर्ग करना बेहतर समझा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवप्रयास समिति का यह कार्यक्रम सराहनीय है।

विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और प्रेरणा से शिक्षा के साथ-साथ हर क्षेत्र में इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी निकल रहे हैं। लगातार तीन वर्ष से यह सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पहले वर्ष 350 दूसरे वर्ष 480 और इस वर्ष 591 प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। 10वीं और 12 वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक और ग्रेजुएट और पोस्टग्रजुएट में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। यह सम्मान खेल, कला, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी कर विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभा दिया जाता है। इस वर्ष डॉ. वीणा सिन्हा, प्रीति खरे, ब्रजेश राजपूत और संजय मेहता को साहित्य सृजन, पत्रकारिता और अभिनय के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। खेल क्षेत्र से वाटर स्पोर्ट्स में आस्था मीणा सहित अन्य प्रतिभाओं सृष्टि गुप्ता, श्रेया मिश्रा, शिवान सिंह सिसौदिया को भी सम्मानित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना करें तैयार

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की साधारण सभा की बैठक में कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि सतत जनभागीदारी और सुव्यवस्थित प्रबंधन का विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण एवं निष्पादन के लिए स्पष्ट नीति तैयार की जाए तथा पंचायतों, ब्लॉक स्तर और क्लस्टर स्तर पर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए तथा अगले 20 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कचरा निष्पादन प्रबंधन के उपाय करें। उन्होंने कचरा परिवहन के लिए वाहनों, एजेंसियों और संचालन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने पर बल दिया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को क्लस्टर आधारित स्वच्छता व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा डस्टबिन के प्रभावी उपयोग, "वॉश ऑन व्हील्स" मॉडल, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और गोबर-धन परियोजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

एनएच-44 पर फिर हादसा....बम्होरी बीका में हाइवा-कंटेनर के बीच हुई जोरदार टक्कर

सागर, (वेब वार्ता)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर फिर बड़ा हादसा हो गया। रविवार देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बम्होरी बीका में एक हाइवा और कंटेनर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाइवा का अगला हिस्सा (केबिन) पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसका चालक उसी में बुरी तरह फंस गया।

हादसे के तुरंत बाद बम्होरी बीका के स्थानीय निवासी और राहगीर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन केबिन इस कदर पिचक चुका था कि चालक को सामान्य रूप से बाहर निकालना नामुमकिन था। ऐसे में एक स्थानीय ग्रामीण ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने ट्रैक्टर को बुलाया। क्षतिग्रस्त केबिन को मजबूत रस्सी से ट्रैक्टर के जरिए खींचा गया और काफी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर

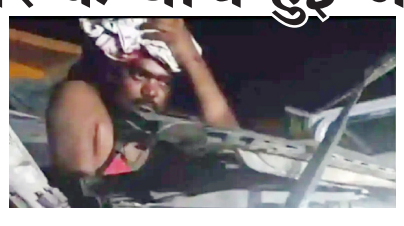

निकाला जा सका। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल चालक को सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ समय में इसी जगह पर यह सातवीं दुर्घटना है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ चल रहा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य ही हादसों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निमार्णाधीन ओवरब्रिज से नीचे उतरते समय एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। नियमतः यहाँ पर्याप्त रिफ्लेक्टर (रात में चमकने वाली पट्टियाँ) और स्पष्ट रोड मार्किंग होनी चाहिए, जो कि गायब हैं। हाईवे पर आ रहे तेज रफ्तार वाहनों को समय रहते सचेत करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर लाइट नहीं लगाई गई है। संकेतक न होने से भारी वाहन अचानक स्पीड ब्रेकर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, जिससे उनके पीछे आ रहे अन्य वाहन अनियंत्रित होकर टकरा जाते हैं। स्पीड ब्रेकर के ठीक आसपास सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। जब भारी लोड वाले वाहन इन गड्ढों से गुजरते हैं, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है।

एफसीआई के चावल की हेराफेरी में राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं

एथेनॉल चावल मामले की प्रारंभिक जांच में राइस मिलर और कंपनी की भूमिका उजागर

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि बालाघाट जिले में एथेनॉल उत्पादन के लिये भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई द्वारा प्रदाय किए गए चावल की कथित हेराफेरी के मामले में मध्यप्रदेश खाद्य विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की न तो कोई भूमिका है और न ही उनका इस प्रकरण से कोई संबंध है।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन योजना भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दरों पर एथेनॉल निमार्ता कंपनियों को चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसके पश्चात एथेनॉल निमार्ता तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की आपूर्ति करते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था में चावल का आवंटन, मूल्य निर्धारण, परिवहन एवं संचालन संबंधी सभी प्रक्रियाएं केंन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती हैं। राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था की इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

श्री राजपूत ने बताया कि बालाघाट जिले में प्राप्त शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में एफसीआई द्वारा एवीजे एग्रिको प्राइवेट लिमिटेड, बोरगांव (जिला छिंदवाड़ा) को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदाय किया गया 242.55 क्विंटल (490 बोरी) चावल ट्रक क्रमांक सीजी 04-जेडी 3147 में संचेती राइस मिल, वारासिवनी (जिला बालाघाट) के परिसर में पाया गया। प्रथम दृष्टया चावल के व्यपवर्तन की पुष्टि होने पर एवीजे एग्रिको प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि तथा संचेती राइस मिल के संचालक के विरुद्ध वारासिवनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

श्री राजपूत ने कहा कि प्रारंभिक जांच में एथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए टीटी चावल की कथित हेराफेरी में संबंधित एथेनॉल निमार्ता कंपनी एवं राइस मिलर की भूमिका सामने आई है। श्री राजपूत ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदाय किए जाने वाले चावल में होने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने तथा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर अविलंब कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जो भी व्यक्ति अथवा संस्था दोषी पाई जाएगी, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रतलाम-इंदौर फोरलेन पर पुलिया के डिवाइडर से टकराई कार, बाल रोग विशेषज्ञ और उनके ससुर की मौत

रतलाम, (वेब वार्ता)। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रतलाम-इंदौर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसे में रतलाम जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष सिंह और उनके 80 वर्षीय ससुर शिवनारायण राजौरिया की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब पूरा परिवार भोपाल से रतलाम लौट रहा था। प्रारंभिक जांच के अनुसार चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर पुलिया के डिवाइडर से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे धराड़ के आगे और टोल प्लाजा से पहले स्थित एक छोटी पुलिया पर हुआ। तेज रफ्तार कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।